श्री शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947
70025-06581

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 205 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पुरुष बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता — पेज 2
सुपरवाइजर नियुक्ति में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 25 फीसदी सीटें होंगी ... — पेज 3
पिछली कांग्रेस सरकार ने ईआरसीएपी को अटकाने और भटकाने का किया काम — पेज 5
बेयरस्टो की जगह लारेंस को शामिल करें : कुक — पेज 7

मैतेई को एसटी में शामिल करने का आदेश एचसी ने किया रद

मणिपुर हिंसा के चलते अबतक 200 की मौत

इंफाल। मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने 27 मार्च, 2023 के आदेश से उस पैराग्राफ को हटाने का आदेश दिया है जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि उक्त पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के रुख के विरुद्ध था। माना जाता है कि हाई कोर्ट के 27 मार्च के उक्त आदेश की वजह से राज्य में जातीय हिंसा भड़की थी जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जस्टिस गोलमेई गाईफुलशिलु की एकल पीठ ने बुधवार को एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश को रद कर दिया। पिछले वर्ष के फैसले में उक्त पैराग्राफ में कहा गया था कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को जल्द से जल्द एसटी सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगी। इसके लिए सरकार को आदेश प्राप्त होने की तिथि से चार हफ्ते का समय दिया गया था। जस्टिस गाईफुलशिलु ने अपने फैसले में एसटी सूची में संशोधन के लिए भारत -शेष पृष्ठ दो पर

मिशन बसुंधरा 2.0 : मुख्यमंत्री ने धेमाजी में भूमि पट्टे वितरित किए

धेमाजी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज एक कार्यक्रम के दौरान धेमाजी में भूमि पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम में बोलते हुए, सीएम शर्मा ने गैर-कैडस्ट्राल गांवों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रमुख मिशन बसुंधरा 2.0 का विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। शर्मा ने कहा कि धेमाजी को मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है, मिशन के दायरे में 38,000 परिवार जोड़े गए हैं, जिसके तहत परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज वितरित किए जाने वाले डिजिटल भूमि पट्टों के महत्व को भी गिनाया क्योंकि इससे न केवल लोगों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी भूमि की स्थिति या अपनी भूमि से संबंधित जानकारी का पता लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि व्यक्ति को कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। 14 नवंबर, 2022 को अपनी शुरुआत के बाद से, मिशन बसुंधरा 2.0 भूमिहीन स्वदेशी लोगों और समाज के कमजोर वर्गों को भूमि का सही स्वामित्व हासिल करके उन्हें सशक्त बनाने में सहायक रहा है। यह कार्यक्रम भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, विकलांग व्यक्तियों, बिना कमाने वाले विधवाओं और बिना नियमित आय वाले कृषकों के लिए कम या आसान प्रीमियम विकल्प प्रदान करता है। मिशन बसुंधरा 2.0 का एक प्राथमिक उद्देश्य वंशानुगत भूमि रखने वाले आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, यह पहल भूमि स्वामित्व की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करती है, जिससे भूमिधारक विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने में सक्षम होते हैं, जिससे ऋण और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ जाती है। सरकार द्वारा नियोजित वितरण कार्यक्रम में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विधान सभा सत्र शामिल हैं। केंद्रीय और राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और मुख्य कार्यकारी सदस्य इसके सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। भूमि पट्टों का वितरण सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में राज्य की -शेष पृष्ठ दो पर

कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया

गुवाहाटी। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) ने हाल के असम विधान सभा सत्र के दौरान कॉलेज प्रवेश नीतियों की कथित रूप से गलत व्याख्या करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। असम विधानसभा के प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि उपरोक्त मामले में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव असम कांग्रेस विधायक दल द्वारा लाया गया था। गुरुवार -शेष पृष्ठ दो पर

बोर्ड परीक्षाओं में *कदाचार* पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने विस में किया हंगामा

गुवाहाटी। असम विधानसभा को गुरुवार को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी दलों ने कथित प्रश्न पत्र लीक सहित राज्य बोर्ड परीक्षाओं में कदाचार के आरोपों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव की मांग को लेकर हंगामा किया। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस और एकमात्र निर्दलीय विधायक ने बहिर्गमन किया क्योंकि अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर अड़े रहे। विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, उनकी कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कक्षा 10 और 12 की राज्य बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में समस्याओं के आरोपों पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए अलग-अलग नोटिस दिए थे, जो वर्तमान में चल रहे हैं। सैकिया ने कहा कि पिछले साल 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसके कारण सरकार को सीआईडी जांच का आदेश देना पड़ा था। उन्होंने यह जानने की मांग की कि सीआईडी -शेष पृष्ठ दो पर

उप्र में आयुष के विकास एवं लोकप्रिय होने की अपार संभावनाएं : सोनवाल

लखनऊ (हि.स.)। केन्द्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में चार दिवसीय तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य-2024 का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परम्परागत चिकित्सा प्रणाली में हम सब सर्वोत्तम है। आयुष हमारी प्राचीनतम उच्च चिकित्सा पद्धति है। यह आज के समय की आवश्यकता और इसकी प्रमाणिकता भी वैज्ञानिक है। केन्द्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि आयुष के विकास का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उन्होंने देश में आयुष के विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्पादन का एक अच्छा ईको सिस्टम तैयार किया है। उन्होंने कहा कि आयुष के विकास के लिए हमारे देश में सभी जगहों पर स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संसाधन है। हम वोकल फार लोकल से ग्लोबल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत आयुष की क्षेत्र में अपने आत्मनिर्भरता सिद्ध करते हुए अपनी आवश्यकतानुसार विश्व को अपने साथ जोड़कर -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

मानव-वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर केंद्र देगी 10 लाख का मुआवजा

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में केरल सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन, वायनाड के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, राज्य के वन और वन्यजीव, पर्यटन और स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर परिवारजन को दी जाने वाली मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए -शेष पृष्ठ दो पर

असम विस : महिला शिशु कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष का बहिर्गमन

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने महिला एवं शिशु कल्याण विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए इस कटौती प्रस्ताव पर अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी ने सदन में चर्चा करने की अनुमति दी। चर्चा में सत्ता तथा विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। विधायकों ने इस दौरान राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे एसएनपी (बच्चों को भोजन) के गुणवत्ता पर सवाल उठाया। सदन में प्रतिपक्ष के नेता देवब्रत सैकिया ने निम्न स्तरीय खाद्य -शेष पृष्ठ दो पर

मंत्री पीयूष ने विपक्ष पर किया हमला

गुवाहाटी (असम)। राज्य विधानसभा से एक साथ बाहर निकलने के लिए कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) पर हमला करते किया है। असम के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने पूछा है कि क्या *दोनों पार्टियां* एक दूसरे के खिलाफ हैं या गठबंधन में हैं। बुधवार को स्पीकर द्वारा गोरुखुटी परियोजना के बारे में एआईयूडीएफ विधायक -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

आग में आग नहीं डालनी चाहिए। अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

तालिबान ने भीड़ के सामने दो को दी मौत की सजा

काबुल। तालिबान ने दक्षिणपूर्वी अफगानिस्तान के एक स्टेडियम में गुरुवार को दो लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी। गजनी शहर के अली लाला इलाके में समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के एक संवाददाता -शेष पृष्ठ दो पर

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर सीबीआई का छापा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के किरु हाइड्रो प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास समेत कुल 30 स्थानों की तलाशी ली। हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्कर्स के टेंडर में घोटाले का आरोप है। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल रहते हुए खास कंपनी को टेंडर देने के लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। वैसे मलिक ने रिश्वत की पेशकश करने वाला नाम अभी तक उजागर नहीं किया है। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार छापे की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में एक साथ की गई और इसमें लगभग 100 अधिकारी शामिल थे। सीबीआई की टीम -शेष पृष्ठ दो पर

मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगी जेड प्लस सुरक्षा

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की खतरे की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा कवर मुहैया कराएगी। बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है।

रिलायंस बना रहा है हनुमान एआई 11 भाषाओं में करेगा काम

नई दिल्ली। चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी एआई को टक्कर देने के लिए अब जल्द ही एक देसी चैटबॉट लॉन्च होने जा रहा है। इस चैटबॉट को रिलायंस डेवेलॉप कर रहा है। जिसे हनुमान के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मकसद बहुत सिंपल है। ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी एआई प्रीमियम सर्विसेज के लिए पैसे लेती है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रिलायंस इस चैट बॉट की सर्विसेज फ्री दे सकता है। रिलायंस का ये मॉडल चार क्षेत्रों स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा में 11 स्थानीय भाषाओं के माध्यम से काम करेगा। ब्लूमबर्ग ने वार्षिक नैसकॉम आईटी उद्योग के मौके पर आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग -शेष पृष्ठ दो पर

अदालत ने 80 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई कुल 45 साल जेल की सजा

नई दिल्ली। केरल में 80 वर्षीय व्यक्ति को कुल 45 साल जेल की सजा सुनाई गई है। राज्य की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए यह सजा सुनाई है। यह मामला केरल के इडुक्की जिले का है। इडुक्की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश टी.जी. वर्गीस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत व्यक्ति को कुल 45 साल की अलग-अलग सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने दी। एसपीपी ने बताया कि चूंकि सजाएं एक साथ काटनी होंगी और दोषी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 20 साल थी, इसलिए वह 20 साल जेल में काटेगा। अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। -शेष पृष्ठ दो पर

भारत की समृद्ध विरासत की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है : पीएम

नवसारी/नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जब भाई-भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार राजनीति का लक्ष्य बन जाता है तो देश की विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत की समृद्ध विरासत की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कपड़ा, बिजली और शहरी विकास के क्षेत्रों में वडोदरा, नवसारी, भरूच और सूरत के लिए विकास परियोजनाओं के लिए नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ से गुजरात की विकास यात्रा को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विकास के साथ-साथ विरासत को प्राथमिकता देने पर सरकार के जोर को रेखांकित किया और कहा कि यह क्षेत्र भारत की आस्था और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र -शेष पृष्ठ दो पर

दारुल उलूम ने गजवा-ए-हिन्द के समर्थन में फतवा जारी किया

जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के दिए आदेश

सहारनपुर (हि.स.)। इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवा-ए-हिन्द को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया है। दारूल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है। इसमें गजवा-ए-हिन्द को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमामंडित किया गया है। इसमें कहा गया है कि गजवा-ए-हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे, जिस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सहारनपुर के जिलाधिकारी व एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। मुख्तार कंपनी द्वारा प्रकाशित सुन्न अल नसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस किताब में गजवा-ए-हिन्द को लेकर एक पूरा चैप्टर है। जिसमें बताया हजरत अबू हुरैराह ने हदीथ के बारे में बताते हुए कहा है कि अल्लाह के मैसेंजर ने *भारत पर हमला* करने का वादा किया था। अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद और अपनी धन सम्पदा को कुर्बान कर दूंगा। मैं सबसे महान बलिदानी बनूंगा। इसमें इस बात का -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

चापर में सात मवेशी एवं एक वाहन जब्त

धुबड़ी (हिंस)। धुबड़ी जिला के शालकोसा पुलिस ने बांग्लादेश में पशु तस्करी रैकेट के खिलाफ छापामारी की। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि अभियान के दौरान में पुलिस ने चापर के चंद्रडिंगा ब्रह्मपुत्र घाट से बीती रात मवेशियों से भरे एक वाहन का पीछा कर जब्त कर लिया। वाहन में 7 मवेशियों को बांग्लादेश की ओर तस्करी के उद्देश्य से लाया गया था। सात मवेशियों की बरामदगी के साथ ही शालकोसा पुलिस ने बोलेरो वाहन (एएस-26सी-6642) को जब्त कर लिया है। हालांकि, गौ माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धुबड़ी जिला के चापर में गौ तस्करी का गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है।

चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पुरुष बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता

गुवाहाटी। पंजाब यूनिवर्सिटी की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक मैच एक अंक से जीता टीम ने मद्रास यूनिवर्सिटी को 85-8 से हराया। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी पुरुष बास्केटबॉल टीम की वापसी एक परी कथा की तरह है। हाल ही में संपन्न ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी जैन यूनिवर्सिटी से हार गई लेकिन गुवाहाटी आकर टीम ने बदला ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में जैन यूनिवर्सिटी को हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रवेश किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरी बार पंजाब यूनिवर्सिटी पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच का पद संभालने वाले डॉ. मनदीप थोर ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि फाइनल में हमेशा दबाव रहता है। इसलिए मैंने लड़कों को प्रेरित किया मेरा एकमात्र निर्देश टीम को दबाव से दूर रखना था हमने पहले मद्रास यूनिवर्सिटी को हराया था, इसलिए हमें विश्वास था कि हम इस बार भी ऐसा कर सकते हैं। इस बीच, पंजाब यूनिवर्सिटी के सफल अभियान का नेतृत्व टीम के चमकते सितारे नवाज सिंह पनाइच ने किया। टीम ने खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं में हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद की है नवाज की भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की इच्छा है और हाल ही में उन्हें चेन्नई में आयोजित होने वाले भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय शिविर के लिए चुना गया है। नवाज सिंह पनाइच ने कहा कि यह बहुत लंबी यात्रा है मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं यह छह से सात साल की योजना थी टीम अभ्यास सुबह 6 बजे शुरू होता है लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अभ्यास से ढाई घंटे पहले शुरू करता हूं।

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर दिग्विजय और डॉ. उदित राज गिरफ्तार

भोपाल (हि.स.)। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मुद्दे को विपक्ष फिर से हवा दे रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद व ईवीएम हटाओ मोर्चा के संयोजक डॉ. उदित राज ने गुरुवार को मार्च निकाला। दिल्ली के जंतर-मंतर में बिना अनुमति धरना करने के लिए उन्हें रायसीना रोड से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि मुझे दो हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा की ओर से 22 फरवरी को शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। यह धरना ईवीएम से देश में लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर था। इसे मैंने स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा कि दो दिन पहले शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई थी। इस अवसर पर उदित राज ने कहा किए ईवीएम के खिलाफ जंतर- मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति रद्द कर दी। हजारों लोगों को पुलिस ने भगा दिया और सैंकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। वैकल्पिक स्थल यूथ कांग्रेस कार्यालय पर हम हजारों जमा हुए, जिनको दिग्विजय सिंह, दीपक बाबरिया, दीपंकर भट्टाचार्य, महमूद पराचा आदि ने संबोधित किया। जब हम प्रदर्शन करना चाहे तो गिरफ्तार कर लिया और अब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में हैं। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के लिए ईवीएम सबसे बड़ा हथियार है। देश के मुख्य न्यायाधीश से मांग करते हुए उन्होंने पूछा कि आपको और क्या सबूत चाहिए? आप घोटालेबाजों और बेईमान लोगों को वीवीपैट ईवीएम में हेरफेर करने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव जीतने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है कि आपने स्वयं यह टिप्पणी की है कि सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है। क्या इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे हैकिंग या हेरफेर की अनुमति मिल सकती है? क्या मैं सही हूं?

बकलियाघाट में लगी आग, सात दुकान और छह गोदाम जले

कार्बी आंगलोंग (हिंस)। राज्य के पहाड़ी जिला कार्बी आंगलोंग के बकलियाघाट बाजार में आज तड़के सहकारी समिति के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में आग लग गई। आग में सात दुकानें और छह गोदाम जलकर राख हो गए। आग कैसे और कहा से लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आग में कपड़े की दो दुकानें, एक बुक स्टॉल, एक होटल और एक किराने की थोक दुकान जलकर राख हो गई। डिफू और हाउराघाट से फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंची, तब तक आग में दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। हादसे में लाखों रुपए का सामान और संपत्ति जलकर स्वाहा हो गयी। इस मामले में लोगों ने मांग की है कि बकलियाघाट में जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड का कार्यालय स्थापित किया जाए। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर नुकसान का आकलन कर रही है।

भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ तीन गिरफ्तार

धेमाजी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के धेमाजी दौरे से पहले पुलिस ने धेमाजी में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 500 ग्राम ड्रग्स जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार को धेमाजी में असम राज्य परिवहन निगम बस स्टैंड से बासंती सना को 10 मादक पदार्थ भरे कंटेनर ड्रग्स बरामद किए। तिनसुकिया के श्रीकृष्ण टी एस्टेट की एक महिला बासंती सना ड्रग्स लेकर आई थी।

मेक्सिको में अपराधियों में टकराव 12 को मौत के घाट उतारा

मेक्सिको सिटी (हि.स.)। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ग्युरेरो में प्रतिद्वंद्वी आपराधिक गिरोहों के बीच भयावह टकराव में कम से कम 12 लोग मारे गए। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की। ओब्रेडोर ने मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, घटना की जांच मंगलवार को शुरू हो चुकी है। नेशनल गार्ड के सैनिक घटनास्थल पर हैं। इस बर्बर झड़प का विवरण बाद में प्रदान किया जाएगा। मेक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि इस घटना का मंगलवार को सामने आया वीडियो दिल दहला देने वाला है। इसमें बंदूकधारी अपने दुश्मनों को गोली और लातें मारने के साथ जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस देश में सिर काटने और फांसी देने के वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। ताजा वीडियो में जंगली पहाड़ी पर आगबबूला बंदूकधारी अपने दुश्मनों पर चिल्ला रहे हैं। उन्हें गाली दे रहे हैं।

SHORT ADVERTISEMENT

THE GAUHATI HIGH COURT AT GUWAHATI
(The High Court of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh)

Online applications are invited from eligible candidates for filling up of **6 (six)** posts of Stenographer Grade-III in the Principal Seat of the Gauhati High Court in the usual scale of pay. All the necessary details viz., important dates, age criteria, reservation and selection process etc. can be seen in the relevant notification published in the official website (**www.ghconline.gov.in**) & Notice Board of Gauhati High Court at Guwahati.

-- Janasanyog /D/18169/ 23/ 23-Feb-24

Sd/-
Registrar (Administration),
Gauhati High Court, Guwahati

पृष्ठ एक का शेष

मैतेई को एसटी ...

सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए उक्त आदेश को हटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तदनुसार, पैराग्राफ संख्या 17(थ्री) में दिए गए निर्देशों को हटाने की जरूरत है और 27 मार्च, 2023 के फैसले व आदेश के पैराग्राफ संख्या 17(थ्री) को हटाने का आदेश दिया जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2013-14 की रिपोर्ट में संवैधानिक प्रोटोकाल का जिक्र करते हुए अदालत ने अपने 19 पृष्ठों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या के साथ तालमेल की जरूरत को रेखांकित किया। साथ ही संविधान पीठ के नवंबर, 2000 में दिए गए निर्णय में एसटी के वर्गीकरण से संबंधित न्यायिक हस्तक्षेप पर विधायी अधिकार क्षेत्र को रेखांकित किया। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि अदालतों को ऐसे वर्गीकरण निर्धारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 27 मार्च, 2023 के आदेश के परिणामस्वरूप भड़की हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिनमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने 17 मई, 2023 के हाई कोर्ट के आदेश को आपत्तिजनक बताया था।

मिशन बसुंधरा 2.0 : मुख्यमंत्री ...

यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ब्रह्मपुत्र घाटी में 3,02,545 बीघे और बराक घाटी में 1,214 बीघे कुल भूमि क्षेत्र का निपटान करके, सरकार ने अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। भूमि पट्टे प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिवारों में से 84 फीसदी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं। यह लक्षित दृष्टिकोण समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान और राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है।

कांग्रेस ने सीएम के ...

को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, सीएलपी नेता देबब्रत सैकिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में एक बहस के दौरान कॉलेज प्रवेश नीतियों के बारे में कोई ठोस जानकारी पेश करने में विफल रहे। देबब्रत सैकिया ने कहा कि बिना जानकारी के बोलने से सदन की अवमानना होती है। इस प्रकार, हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। इस बीच, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव को लिखे पत्र में, प्रधान सचिव ने इस विषय पर अपने विचार जानने के लिए इसे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने और असम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में एक तथ्यात्मक नोट जमा करने का आग्रह किया। संबंधित मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु।

बोर्ड परीक्षाओं में ...

की जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए। इस बार भले ही पेपर लीक नहीं हुआ हो, लेकिन परीक्षा के पहले दिन से ही प्रश्नपत्र बंडलों पर गलत लेबलिंग और ऐसी अन्य गलतियों की खबरें आ रही हैं। हम विभाग के लिए धन आवंटित करेंगे लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि कांग्रेस नेता ने कहा। हालांकि, गोगोई ने आरोप लगाया कि इस साल भी एक प्रश्नपत्र लीक हो गया है और परीक्षा के संचालन में समस्याओं का संकेत देने वाली समाचार पत्रों की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने इस मामले पर शिक्षा मंत्री रनोज पेगु के इस्तीफे की भी मांग की। स्पीकर विश्वजीत दैमारी ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि हालांकि मामला महत्वपूर्ण है, इस पर अन्य प्रावधानों के तहत चर्चा की जा सकती है और सरकार इसका जवाब दे सकती है। संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने सदन में कहा कि इस साल कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है। हालांकि, विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और हंगामा बढ़ने पर दैमारी ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तो कांग्रेस विधायकों और गोगोई ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और बहिर्गमन किया क्योंकि अध्यक्ष ने उनके प्रस्ताव को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मानव-वन्यजीव संघर्ष ...

कर दी है। बैठक में भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधीन कोयंबटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में मानव वन्यजीव संघर्षों के शमन पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केरल राज्य को विभिन्न योजनाओं के तहत 15.82 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बैठक में केंद्र सरकार भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करेगी। हाथी रोधी बाड़ का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण फैसले में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने, स्थानांतरित करने या शिकार करने की अनुमति के संबंध में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 राज्य प्रमुख डब्ल्यू को अधिकार दे दिया है। उल्लेखनीय है कि वायनाड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (जो वायनाड से सटा हुआ है) और केरल के वायनाड का दौरा किया।

असम विस : महिला...

उपलब्ध करवाने के मामले की जांच कराने तथा एक सदन कमेटी बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे एसएनपी के मेन्यू में बदलाव करवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं के वेतन बढ़ाने संबंधी विभागीय निदेशक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री अजंता नेओग से सदन में आश्वासन मांगा। वहीं, कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन ने मॉडल सेंटर के निर्माण में सभी विधायकों को समान रूप से शामिल नहीं करने का सवाल उठाया। विधायक अखिल गोगोई ने एसएनपी मैं हो रही गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की। उन्होंने साथ ही प्रस्तुति तथा नवजात शिशु के मृत्युदर में असम का देश के भीतर चौथे स्थान होने की भी बात कही। विधायक भारत चंद्र नरह ने असम में आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं का वेतन देशभर की तुलना में सबसे कम होने तथा एसएनपी की गुणवत्ता की जांच कराने संबंधी मांग की। वहीं विभिन्न सदस्यों ने मॉडल सेंटर के निर्माण चाय बागान तथा चर क्षेत्र में कराने, आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने आदि की मांग सदन में उठाई। चर्चा के अंत में राज्य की समाज कल्याण मंत्री अजंता नेओग ने विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का उत्तर दिया। विपक्षी सदस्यों द्वारा बीच-बीच में होती रही टोका-टोकी एवं गर्मा-गर्मी के बीच विभागीय मंत्री ने अपना पूरा उत्तर दिया। उत्तर से संतुष्ट नहीं होकर विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक अखिल गोगोई समेत अनेक विपक्षी विधायकों ने सदन से वर्कआउट कर दिया। इसके बाद सदन में मौजूद सदस्यों के बीच बहुमत से कटौती प्रस्ताव को सदन के पटल से उठा लिया गया। विपक्ष के बहिर्गमन के बीच विधानसभा अध्यक्ष दैमारी ने समाज कल्याण मंत्री अजंता नेओग के विभागीय मंजूरी प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से पारित कराया। इसके साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी इस दौरान पारित किए गए।

मंत्री पीयूष ने ...

द्वारा पूछे गए सवाल पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार करने के बाद दोनों दलों ने वाकआउट किया। हजारिका ने कहा कि कांग्रेस हर बार एआईयूडीएफ को निशाना बनाती है और एआईयूडीएफ कांग्रेस को निशाना बनाती है। कांग्रेस कहती है कि एआईयूडीएफ सांप्रदायिक है और एआईयूडीएफ कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन आज हम आश्चर्यचकित हैं कि एआईयूडीएफ विधायक ने एक सवाल उठाया और कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों एक साथ बाहर चले गए। हजारिका ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ हैं या गठबंधन में हैं। क्या कांग्रेस और एआईयूडीएफ का नया गठबंधन बनने जा रहा है, यह मेरा सवाल है। मैं उनसे तुरंत जवाब चाहता हूं। बता दें कि इससे पहले एआईयूडीएफ नेता अमीनुल इस्लाम ने गोरुखुटी कृषि परियोजना को लेकर सदन में सवाल उठाया था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कांग्रेस समेत एआईयूडीएफ विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।

उप्र में आयुष के ...

एक वैश्विक समाज का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के आयोजन से हमें अपने आयुष के जीवनशैली को वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होंगे। इस तरह आयुष के प्रोत्साहन से हम सम्पूर्ण मानवता को खुशहाली की ओर ले जा पायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी आयुष पद्धति को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने मान्यता दी है और परम्परागत चिकित्सा पद्धति में हम शिखर पर है। इसकी वैज्ञानिकता भी सिद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आयुष के लिए एक अच्छा वातावरण है। उप्र भारत का एक खूबसूरत राज्य है। भारत में आयुष के विकास होने से भारत को बल्कि सभी देशों को समान लाभ मिलेगा। केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री मंजूपारा महेन्द्र भाई ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष के क्षेत्र में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। आयुष के प्रोत्साहन के साथ-साथ परम्परागत औषधियों के उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने सम्बोधन में कहा कि आयुष हमारे देश की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। राज्य सरकार इस प्रणाली को लोकप्रिय बनाने तथा जन-जन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। इस पद्धति को और प्रमाणिक, सुलभ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। विभिन्न जनपदों में आयुष के 4000 चिकित्सालय लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। योग एवं नेचुरोपैथी के उत्कृष्ठ शोध को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है। इस चिकित्सालय में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी की ओपीडी सेवायें शुरू हो गयी हैं। उन्होंने इस चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय आरोग्य-2024 के आयोजन के लिए केन्द्रीय मंत्री आयुष एवं राज्यमंत्री आयुष का आभार जताया। प्रमुख सचिव आयुष लीना जौहरी ने कहा कि आयुष एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवनपद्धति है। इसके विकास के साथ-साथ सम्पूर्ण मानवता के निरोग एवं स्वस्थ बनाने के लगातार प्रयासरत हैं। मुझे खुशी है कि इस चार दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने तथा शोध को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल...

सुबह-सुबह सत्यपाल मलिक के दिल्ली के आरके पुरम स्थित घर के साथ द्वारका और एशियन गेम्स विलेज के साथ-साथ गुरुग्राम और बागपत स्थित ठिकानों की भी तलाशी ली। जिन स्थानों की तलाशी ली गई, उनमें सत्यपाल मलिक के करीबी भी शामिल हैं। इसके साथ ही चेनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी और ठेका पाने वाले पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अधिकारियों के यहां भी छापे मारे गए। वैसे छापे के दौरान खुद सत्यपाल मलिक घर पर उपस्थित नहीं थे। एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट कर उन्होंने बताया कि वे पिछले तीन चार दिनों से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके ड्राइवर और सहयोगी के ठिकानों की भी तलाशी ली गई है। उन्होंने छापे को सरकार की तानाशाही बताते हुए कहा कि वे किसान के बेटे हैं और छापों से नहीं डरते हैं। मलिक अगस्त 2018 से अक्तूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटते हुए केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने किरु हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ ही एक अन्य प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के एवज में कुल 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज जांच शुरू की है। सीबीआई की एफआईआर में चेनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी समेत कई अधिकारियों एमएस बाबु, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही ठेका पाने वाली कंपनी पटेल इंजीनियरिंग को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई पहले भी की स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है।

रिलायंस बना रहा ...

विभाग के अध्यक्ष गणेश रामकृष्णन के हवाले से कहा कि मॉडल *हनुमान* चैटबॉट लार्ज लैंग्वेज मॉडल की पेशकश करेगा, इसके पास स्पीच टू टेक्सट यूजर फ्रेंडली फीचर भी होगा। लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और अरबपति विनोद खोसला के फंड जैसे प्रमुख वीसी निवेशकों द्वारा समर्थित सर्वम और क्रुट्रिम जैसे कुछ अन्य स्टार्टअप भी देश के लिए अनुकूलित ओपन-सोर्स एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जियो विशिष्ट उपयोगों के लिए अनुकूलित मॉडल बनाने की योजना बना रहा है। टेलीकॉम-टू-रिटेल समूह पहले से ही *जियो ब्रेन* पर काम कर रहा है, जो लगभग 450 मिलियन ग्राहकों के नेटवर्क पर एआई का उपयोग करने के लिए एक मंच है। दो महीने पहले जियो इंफोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया था कि कंपनी टेलीविजन के लिए जियो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने पर विचार कर रही है।

अदालत ने 80...

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि दोषी से यह जुर्माना मिला है तो उसे पीड़िता को दिया जाना चाहिए। अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लड़की के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। एसपीपी ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। जब यह घटना घटी तब लड़की के घर पर कोई नहीं था। लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी थी जबकि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। लड़की की देखभाल एक बुजुर्ग दंपती कर रहा था जो उसके पिता के रिश्तेदार थे। दरअसल, पीड़िता के घर के पास दोषी व्यक्ति की दुकान थी। एक दिन जब व्यक्ति ने देखा कि लड़की के घर पर कोई नहीं है, तो वह घर में घुस गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

भारत की समृद्ध ...

निर्माण। उन्होंने भाई-भतीजावाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति के कारण क्षेत्र की विरासत की उपेक्षा पर भी अफसोस जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके विपरीत, भारत की समृद्ध विरासत की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। *मोदी की गारंटी* को लेकर चल रही चर्चा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा दी गई गारंटी के पूरा होने की निश्चितता को रेखांकित किया कि यह बात गुजरात के लोगों को लंबे समय से पता है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है और ये गारंटी सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं है बल्कि जो हकदार हैं उन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की गारंटी है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी भी वो गाली देंगे, हमारा 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेकेंगे, 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कांग्रेस के पास मोदी को गाली देने के अलावा विकास का कोई एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री ने *फाइव एफ* को याद किया, जिसके बारे में वह अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान बात करते थे। इसका मतलब- फॉर्म, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्टरी, फैक्टरी टू फैशन, फैशन टू फॉरेन था। अर्थात किसान कपास उगाएगा, कपास फैक्टरी में जाएगा, फैक्टरी में बने धागे से परिधान बनेंगे और यही परिधान विदेशों के लिए निर्यात होंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज एक प्रकार से सूरत सिल्क सिटी का विस्तार नवसारी तक हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मित्र पार्क के पूरा होने से पूरे क्षेत्र का चेहरा बदल जाएगा, जहां केवल इसके निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पार्क श्रमिकों के लिए घरों, लॉजिस्टिक्स पार्क, गोदाम, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशिक्षण और कौशल विकास की सुविधाओं से सुसज्जित होगा। प्रधानमंत्री ने 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले तापी नदी बैराज के शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आने वाले वर्षों में सूरत में जल आपूर्ति से संबंधित समस्याएं हल हो जाएंगी। साथ ही बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से उबरने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जनसमहू को पीएम सूर्यघर योजना के बारे में बताया जो न केवल घरों के ऊर्जा बिल को कम करेगी बल्कि आय उत्पन्न करने का माध्यम भी बनेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन इस क्षेत्र से होकर गुजरेगी, क्योंकि यह क्षेत्र देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों-मुंबई और सूरत को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत नवसारी के किसानों को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी और तटीय गांवों की पहले की उपेक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने उमरगाम से लेकर अंबाजी तक के क्षेत्र में हर बुनियादी सुविधा सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी, 100 से अधिक आकांक्षी जिले जो विकास के मापदंडों में पीछे थे, वे देश के बाकी हिस्सों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया पहल की सफलता और दायरे पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया डिजिटल इंडिया को पहचानती है। उन्होंने कहा कि ये वही डिजिटल इंडिया है, जिसका कांग्रेस के लोग कभी मजाक उड़ाया करते थे। आज डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है।

दारुल उलूम ने ...

भी जिक्र किया गया है कि देवबंद की मुख्तार कंपनी ने इस किताब को प्रिंट किया है। जिस पर एनसीपीसीआर ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए सहारनपुर के डीएम और एसपी को कार्रवाई के लिए लिखा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को एक नोटिस जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। एनसीपीआर ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षाएं दे रहा है। इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। आयोग ने इसे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन करार दिया है। एनसीपीसीआर ने सीपीसीआर अधिनियम की धारा 13 (1) टीजे) के तहत मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस तरह के फतवे की सामग्री से देश के खिलाफ नफरत फैल सकती है। आयोग ने जिला प्रशासन से दारुल उलुम की बेवसाइट की जांच करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इसके जरिए देश की जनता को गुमराह किया गया है। इसलिए इस वेबसाइट की जांच कर इसे तुरंत ब्लॉक किया जाए। इसके साथ ही एनसीपीसीआर ने चेताया है कि जल्द ही इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो खुद जिला प्रशासन भी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा। दारुल उलूम देवबंद में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से *गजवा ए हिन्द* किया जाए। जो भी गजवा-ए-हिन्द के लिए अपनी जान देगा वो सर्वोच्च बिलदानी कहा जाएगा। ये संस्था पूरे दक्षिण एशिया में मदरसों को संचालित करती है।

तालिबान ने भीड़ ...

समेत हजारों लोगों की मौजूदगी में दोनों लोगों को गोली मार कर मौत की सजा दी गई। तालिबान ने दोनों लोगों के कथित अपराधों तथा उनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि कई अदालतों और तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा ने दोनों लोगों द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए उन्हें मौत की सजा देने का आदेश दिया था। फांसी वाली जगह के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और अंदर जाने के लिए लोग बेसब्र हो रहे थे। इसके अलावा धार्मिक विद्वानों ने पीड़ितों के रिश्तेदारों से दोषियों को माफ करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दोपहर करीब एक बजे एक व्यक्ति को आठ गोलियां मारी गईं जबकि दूसरे को सात गोलियां मारी गईं।

भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस के कई नेता : भवेश कलिता

गुवाहाटी (हिंस)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता ने कहा है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी चर्चा चल रही है। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदलै के भाजपा में शामिल होने की चर्चा संबंधी सवाल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अब तक यह निश्चित नहीं किया गया है कि पार्टी किन-किन नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दे सकती है। हालांकि, उन्होंने यह अवश्य कहा कि इस संबंध में चर्चा चल रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस में रहकर स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्षों को पार्टी के बड़े कार्यक्रमों तक की जानकारी नहीं दी जाती है। कांग्रेस में नेता की बात नहीं चलती है, सभी मनमानी करते हैं। ऐसे में इन नेताओं के कांग्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं होता है।

सुपरवाइजर नियुक्ति में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 25 फीसदी सीटें होंगी आरक्षित : वित्त मंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। वित्त मंत्री अजंता नेओग ने कहा है कि राज्य के महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में होने वाली सुपरवाइजरों की नियुक्तियों में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर विचार करने का सरकार ने निर्णय लिया है। वित्त मंत्री आज असम विधानसभा के चालू बजट सत्र में महिला एवं शिशु विकास विभाग से संबंधित विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की आबादी 49 फ़ीसदी है। ऐसे में महिलाओं के विकास के बिना असम के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विभाग का दायित्व देते हुए उन्हें कहा था कि इस विभाग में नयापन लाना है। इसके लिए वह पहले दिन से ही प्रयास कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं के प्रति सहानुभूति रखती है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि देश में पहली बार असम सरकार द्वारा अवकाश प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को क्रमश: चार लाख, तीन लाख तथा दो लाख रुपए की एककालीन आर्थिक सहायता दी गई है। इसके तहत असम सरकार ने 1856 आंगनबाड़ी कर्मियों तथा 1860 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को एककालीन सहायता देने पर 112 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि शिशु विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसे चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 688.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से असम सरकार को 211.14 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों को 6500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 4750 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3250 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 2500 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य में 10 हजार मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवा रही है। इसमें से पांच हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सभी विधायकों से सूची मांगी गई है, जिसे नाबार्ड को भेजा जाएगा। इस पर विधायक रकीबुल हुसैन ने कहा कि उनसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित कोई लिस्ट नहीं मांगा गया। जबकि, विधायक शेरमान अली ने कहा कि उन्हें सबसे कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ही दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक हजार और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण करने की असम सरकार की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार राज्य के 30 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस दौरान वित्त मंत्री ने विधायकों के कई अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

होल्डिंग टैक्स नहीं तो पानी का कनेक्शन नहीं: मेयर

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) के मेयर मृगेन शरणिया ने कहा है कि जबतक कोई व्यक्ति अपने घर का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करता है तब तक उसे पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस टैक्स, बिजली बिल आदि की वसूली को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। मेयर शरणिया आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का बिजली बिल समय पर जमा नहीं करता है तो उसके घर का होल्डिंग नंबर तथा उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसी बीच गुवाहाटी नगर निगम द्वारा राजधानी के कई मकान मालिकों को संपत्ति अटैच करने संबंधी नोटिसें भी भेजी जा चुकी है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गोलीबारी में पशु तस्कर की मौत

दक्षिण सालमारा (हिंस)। भारत-बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा दक्षिण सालमारा-मानकाचर जिला के मानकाचर में की गई गोलीबारी में एक पशु तस्कर की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि मृत तस्कर की पहचान मानकाचर थाना क्षेत्र के कुकुरमारा चर में रहने वाले शाहीनूर इस्लाम (26) के रूप में हुई है। यह घटना बीती रात उस समय हुई जब, मृतक द्वारा मवेशियों की तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने तस्कर को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भागने लगा। अंधेरे में उसे रोकने के लिए

ऑयल वीडीपी सुरक्षाकर्मियों ने शुरू की 36 घंटे की भूख हड़ताल

तिनसुकिया (हिंस)। दुलियाजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय के सामने आज विरोध-प्रदर्शन किया गया। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में तेल वीडीपी सुरक्षाकर्मियों ने आज 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। खासकर ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कंपनी लिमिटेड के सुरक्षा कार्य में चौबीसों घंटे अपनी ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मियों को लंबे समय से वीडीपी के नाम पर मात्र एक सौ रुपए प्रतिदिन देकर ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं और श्रमिकों के लिए उचित बकाए की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहले से ही अपनी मांगों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से अपील कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन, आज तक संबंधित अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। आखिरकार उन्होंने 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है।

कामरूप जिले में लोस चुनाव की तैयारियां जोरों पर

रंगिया (विभास)। आगामी चुनाव की तैयारियों के अंश स्वरूप आज कामरूप निर्वाचन जिले के अंतर्गत चारों विधानसभा के लिए तैनात सेक्टर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय, अमीनगांव के बैठक कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिले के 27 नम्बर समरिया विधानसभा क्षेत्र, 28 नंबर बोको-छयगांव क्षेत्र, 29 नंबर पलाशबाड़ी क्षेत्र और 30 नंबर हाजो-शुवालकुची निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत जिन मतदान केंद्रों पर ढांचागत समस्याएं हैं या नाम सुधार जैसे मुद्दे हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। बैठक में इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए पर्याप्त उपाय करने पर जोर दिया गया ताकि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि कामरूप निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत इन विधानसभा क्षेत्रों में 964 मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों को 120 सेक्टरों में बांटा गया है और इनके लिए 120 सेक्टर अधिकारी तैनात किये गये हैं। बैठक में प्रभारी जिला आयुक्त नरसिंह बे, अतिरिक्त आयुक्त श्यामंत रबी बारा और कमल बरुआ, चुनाव अधिकारी मानस प्रतिम बोरा, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग, असम राज्य बिजली वितरण निगम के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रत्येक मतदान केंद्र के सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे।

श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के एक माह पूर्ण होने पर असम प्रदेश तैलिक साहू महासभा ने निकाली झांकी

गुवाहाटी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जिसे सारे विश्व में बड़े उत्साह और श्रद्धा से देखा गया, और 17 जनवरी से ही लोगों ने अपने अपने तरीके से घरों, वाहनों इत्यादि पर भगवा झंडा लहराकर, झांकी निकालकर, दीप जलाकर श्री राम के आगमन की उत्सव मनाई। लोगों में उत्साह इतना ज्यादा बना हुआ है कि घरों और वाहनों पर भगवा झंडा अब तक फहराया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के एक महीने पूरे होने पर इसी उत्साह और श्रद्धा के साथ 22 फरवरी 2024 को भगवान श्री राम की एक भव्य झांकी गुवाहाटी

महानगर में असम प्रदेश तैलिक साहू महासभा द्वारा निकाली गई जिसमें ऑल असम ओबीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर गोगोई के अलावा तैलिक साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सहसचिव सत्य नारायण साहू, महामंत्री उमेश कुमार साह, संगठन सचिव परशुराम गुप्ता, बृहत्तर गुवाहाटी महानगर के अध्यक्ष चंपालाल शाह, कालापहार फटासिल लालगणेश के प्रभारी निलाम्बर साहू, कालापहार फटासिल लालगणेश के कोषाध्यक्ष अजय साहू, महेंद्र साहू, राम बहादुर साहू, आशुतोष प्रसाद, आकाश साहू, मुकेश साहू, पीतांबर साहू, उमेश प्रसाद साह, राहुल गुप्ता, मनीष शाह, राखी पाल, दिगंबर साहू, जुनमोनी कलिता, सुनिधि साहा, चंपा बनर्जी, पुष्पा साह, बापन घोष, दिलीप साहू, आलोक साहू और अनेकों ने हर्षोल्लास के साथ श्री राम की जयकारा कर आसमान गुंजायमान और करतल ध्वनि करते हुए भाग लिया। श्री अमरनाथ सेवा समिति के बैनर तले 10 मार्च को मां कामाख्या धाम यात्रा और 16 एवम 17 मार्च को वशिष्ठ में कलश यात्रा और अष्टयाम यज्ञ में भी तन मन धन से भाग लेने का निश्चय इस संस्था द्वारा किया गया और सभी धर्मप्राण बंधुओं से भी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर योगदान का आह्वान किया गया है।

2047 के विकसित राष्ट्र और विकसित रेल विषय पर आयोजित की स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं

गुवाहाटी (हिंस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) में अमृत भारत स्टेशन योजना के अधीन 23 स्टेशनों का पुनर्विकास, 06 रोड अंडर ब्रिज और 02 रोड ओवर ब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अधीन स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली उन्नत और आधुनिक सुविधाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए, पूसीरे द्वारा *2047 का विकसित राष्ट्र और विकसित रेल* विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढकर हिस्सा लिया। पूसीरे के सीपीआरओ सब्यसाची दे ने आज बताया है कि पूसीरे के क्षेत्राधिकार के अधीन 91 से अधिक स्कूलों के कुल 12, 510 छात्र-छात्राओं ने भाषण, निबंध, कविता लेखन, वाद-विवाद और चित्रकारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में 1058 छात्र-छात्रा विजेता बने। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को संबंधित स्थानों पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में विजेता छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सकारात्मक मान्यता निश्चित रूप से उन्हें भविष्य में समाज के लाभ के लिए कार्य करने को बढ़ावा और प्रोस्ताहित करेगी। साथ ही, यह भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानने और समझने को प्रोत्साहित करेगा।

नगरबेड़ा : बिमला प्रसाद चालिहा कॉलेज में आयोजित समारोह में बाल वैज्ञानिक प्रोफेसर सुवर्णा आईजाक बारी ने लिया भाग

नगरबेड़ा (विभास)। सुदुर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दुनिया के सबसे कम उम्र के बाल वैज्ञानिक प्रोफेसर सुवर्णा आइजैक बारी ने आज कामरूप जिले के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक, नगरबेरा के बिमला प्रसाद चलिहा कॉलेज में एक समारोह में भाग लिया। *ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड* से सम्मानित प्रोफेसर सुवर्णा आईजाक बारी कॉलेज के अधिकारियों द्वारा अपने परिसर में छात्रों के साथ आयोजित एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र में बोल रही थीं। कार्यक्रम को कॉलेज के प्रोफेसर इन्को देवी, डॉ. भूषिता पटवारी और मनीषा बोरो ने संबोधित किया और प्रिंसिपल डॉ. कमल चंद्र पाठक ने संबोधित किया। दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर ने छात्रों के विभिन्न सवालों के जवाब देकर भौतिकी और गणित के बारे में अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से सभी को प्रेरित

किया। मीडिया से बात करते हुए बाल वैज्ञानिक ने कहा कि उनकी भविष्य की योजना दुनिया को गणित के जादू से प्रेरित करने की है। उन्होंने नगरबेरा के लोगों के प्यार, स्नेह और प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी बात की जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। सुवर्णा के साथ उनके पिता रशीदुल बारी, जो उपस्थित थे, को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेज प्राधिकरण, नगरबेरा क्षेत्रीय मौजा समिति, नगरबेड़ा रस मंदिर समिति आदि की ओर से औसत के प्रतीक के साथ सम्मानित किया गया, फूलम गमसा, कलम और शरई, पोशाक आदि। ध्यान दें कि बाल वैज्ञानिक ने विचारों के आदान-प्रदान से पहले कॉलेज के वर्ष 2023-2024 के लिए *फल्गु* शीर्षक से एक वॉल पेपर भी जारी किया।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर गूगल मीटर पर काव्य संध्या का आयोजन

विश्वनाथ चाराली (विभास)। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति गूगल मीट पर कल काव्य संध्या का आयोजन किया। अकादमी के संस्थापक एवं अध्यक्ष रीता सिंह *सर्जना* की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. गोमा देवी शर्मा की सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम का संचालन क्रमश: कल्पना देवी आत्रेय और संतोष कुमार महतो ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असम के नेपाली भाषा के वरिष्ठ नाटककार पूर्ण कुमार शर्मा तथा विशिष्ठ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवक डॉ. देवीदास वामणे उपस्थित थे। संस्थापिका ने सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी तथा मातृभाषा दिवस

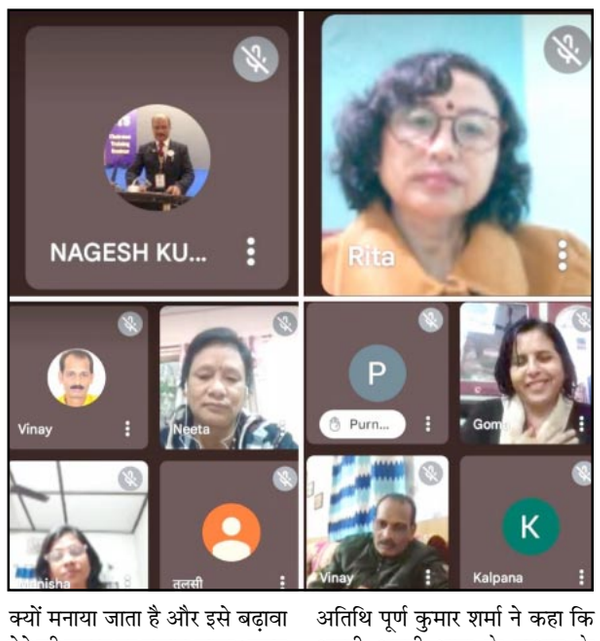

क्यों मनाया जाता है और इसे बढ़ावा देने की जरुरत पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि पूर्ण कुमार शर्मा ने कहा कि अपनी-अपनी भाषा के उत्थान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। मातृभाषा का महत्व को समझकर इसके संरक्षण करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर अपनी मातृभाषा नेपाली में एक पर्यावरण कविता की प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र से पधारे विशिष्ट अतिथि डॉ. ने कहा कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा निज भाषा अहे सब उन्नति का मोल। उन्होंने मराठी के प्रसिद्ध कवि/ साहित्यकार विष्णु वामन शिरवाडकर की कविता *कणा* का पाठ किया। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से उपस्थित भारतीय भाषाओं के कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं अपनी-अपनी मातृभाषा हिंदी, असमिया, नेपाली, भोजपुरी बोडो, मराठी, में वाचन करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिए। भाषा अनेक पर भाव संप्रेषण में प्रवल रूप से सफल। उपस्थित कविगण क्रमश: डॉ. अनिता पंडा (शिलांग), पूर्ण कुमार शर्मा (विश्वनाथ), डॉ. देवीदास वामणे (महाराष्ट्र), मनीषा पाल (विश्वनाथ), राजु बड़ो (उदालगुड़ी) डॉ. गोमा देवी अधिकारी (तेजपुर), जयश्री बड़ो (कोकराझाड़), विनय कुमार *बुद्ध* (बंगाईगांव)कल्पना देवी आत्रेय (नगांव), तुलसी छेत्री (उदालगुड़ी) कागो मादो (अरुणाचल प्रदेश), नीता गुरूंग (गुवाहाटी), दीपा राय (सिक्किम), सीमा सिंह स्वास्तिका (शिलचर) नागेश कुमार गुप्ता (विश्वनाथ), रीता सिंह सर्जना (तेजपुर) संतोष कुमार महतो (विश्वनाथ) और श्रोता के रूप में मानव दे, बेददीप उपाध्याय, दिव्य ज्योति बरुआ उपस्थित थे। संचालन विश्वनाथ जिला इकाई जिलासचिव संतोष कुमार महतो ने कार्यक्रम में चार-चांद लगाने के लिए अतिथि, कवि, श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापन की।

मातृभाषा-राज्यभाषा कार्यान्वयन समिति ने किया मातृभाषा दिवस आयोजित

अपनी मां से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा को नजरअंदाज नहीं कर सकता : भास्कर भट्ट

रंगिया (विभास)। जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान करता है और उसकी सेवा करता है, वह कभी भी अपनी मातृभाषा का अनादर नहीं कर सकता। यह बात नलबाड़ी महाविद्यालय के असमिया विभाग के सहायक प्रोफेसर भास्कर भट्ट ने कही, उन्होंने कहा कि जो अपनी मातृभाषा का अपमान करता है, वह अपनी मां का भी अपमान करता है जिस तरह बच्चे के विकास के लिए मां का दूध जरूरी है, उसी तरह बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा भी जरूरी है। मातृभाषा के सम्मान के नाम पर श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात मातृभाषा राज्यभाषा प्रयोग समिति के सौजन्य से रंगिया के रनदिया (शतदल) साहित्य सभा, कोठोरा हायर सेकेंडरी स्कूल और शहीद सुनंद शालोई मध्य इंग्लिश स्कूल के सहयोग से आयोजित *अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस* में संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित होकर श्री भट्ट ने कही। असम साहित्य सभा की मातृभाषा राज्यभाषा प्रयोग समिति के संयोजक हेमंत कलिता के संचालन में आयोजित एक खुली सभा मे कोठोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता पंकज पल्लव शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। इस कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा अतिथियों का फुलाम गमोछा और ग्रंथ देकर

स्वागत किया गया। बैठक का आधिकारिक उद्घाटन रंगिया शिक्षा खंड के उप निरीक्षक मैनुल हक चौधुरी ने किया। वहीं कामरूप जिला साहित्यिक के अध्यक्ष डॉ. नृपेंद्र नाथ तालुकदार, मध्य पांडुरी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के विधालय के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम डेका, शहीद सुनन्द शालोई मध्य अंग्रेजी विद्यालय के प्रधान शिक्षक गजेन चन्द्र लहकर, कामरूप जिला साहित्य सभा के मातृभाषा राज्यभाषा उप समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष बिरेन कलिता, संयोजक हेमंत कुमार, हरदत्त वीरदत्त स्वर्ण साहित्य सभा के सलाहकार धीरेश्वर डेका, अध्यक्ष हरेश्वर डेका ने संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि असम साहित्य सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रधान संपादक क्रमश: पद्मश्री डॉ. सूर्यकांत हजारिका, डॉ. गिरीश संदीकै और डॉ. उपेन्द्रजीत शर्मा ने सम्मेलन में अभिनंदनात्मक और जरूरी भाषण दिये। कार्यक्रम में रनदिया शतदल साहित्य सभा की आजीवन सदस्या बिमला देवी, बाल कलाकार हिया हिमाश्री दास, संजीव लहकर, राजू कलिता के गीतों ने सबका मन मोह लिया। कोठोरा उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति दी गई चिर सेनेही मोर भाषा जननी नामक गीत से बैठक की शुरुआत की गयी। कार्यक्रम के पूर्व मौके पर रनदिया शतदल साहित्य सभा के अध्यक्ष जयंत जीत कलिता द्वारा साहित्य सभा का ध्वजारोहण और प्रधान शिक्षक गजेन चन्द्र लहकर, शिक्षक क्रमश: जीतेन दास और विनय भट्ट द्वारा भाषा साहित्य के स्वर्गीय सदस्यों की स्मृति में दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित की गई। साहित्यिक कार्यकर्ता, पत्रकार तथा साथ ही साहित्य सभा के आजीवन सदस्य भास्कर कलिता, नारेश्वर राजवंशी, खाईरुल हुसैन, कोठोरा उच्चत्तर माध्यमिक विधालय और शहीद सुनंद शालोई मध्य अंग्रेजी विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी, रनदिया साहित्य साहित्य सभा के कार्यकर्ता, सौ से भी अधिक छात्र-छात्राएं साथ ही कई गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। सभा मे मातृभाषा-राज्यभाषा प्रयोग समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जयन्त माधव बोरा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के अंत में रनदिया शतदल साहित्य सभा के अध्यक्ष जयंत जीत कलिता के कृतज्ञता और धन्यवाद के बाद जातीय संगीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

NOTICE

As per the Advertisement no. KPE.07/2021/100 dated 16.03.2023 and Corrigendum no. KPE.07/2021/103 dated 17.03.2023, the following Candidates are provisionally selected for appointment to the post of **Land Record Assistant** in the amalgamated establishment of the District Commissioner, Kamrup Metropolitan District, Guwahati.

Sl.	Name of Candidate	Roll Nos.	Selected under Category
1.	Sri Nilutpal Dutta	LRAKM-056	UR
2.	Sri Mrinal Jyoti Das	LRAKM-159	UR
3.	Sri Nilutpal Sarmah	LRAKM-069	UR
4.	Sri Saurabh Medhi	LRAKM-043	UR
5.	Sri Kishor Kumar Deka	LRAKM-133	UR
6.	Sri Rakesh Saikia	LRAKM-001	OBC
7.	Sri Nabajyoti Das	LRAKM-158	OBC
8.	Sri Dhruba Jyoti Saikia	LRAKM-208	OBC
9.	Sri Manash Pratim Barman	LRAKM-076	OBC
10.	Sri Abinash Thakur	LRAKM-198	OBC
11.	Sri Dhritiman Ray Medhi	LRAKM-098	OBC
12.	Sri Dhiraj Kherkatari	LRAKM-109	ST(P)
13.	Smti. Sunuma Boro	LRAKM-169	ST(P)
14.	Sri Ridip Kumar Boro	LRAKM-212	ST(P)
15.	Sri Chaw Chawnoi Thumung	LRAKM-094	ST(H)
16.	Smti. Pinky Rahang	LRAKM-137	ST(H)
17.	Sri Biswajit Naiding	LRAKM-065	ST(H)

The above candidates will be appointed temporarily subject to satisfactory Police Verification Report, Medical Fitness Certificate and submission of necessary declaration/affidavits, etc.

District Commissioner
Kamrup Metropolitan District
Guwahati

-- Janasanyog /D/18213/23/23-Feb-24

संपादकीय

संदेशखाली की दरिंदगी

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके के हालात को देख-सुन कर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पहले ही देखा, भोगा और अनुभव किया है। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां 'दरिंदों' के अत्याचार, यौन उत्पीडऩ और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसएस का अड्डा है और वही औरतों को उकसा और बरगला रहा है। यदि संघ किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आश्चर्य यह भी है कि संदेशखाली की औरतों पर सालों से अत्याचार, अनाचार किए जा रहे थे, लेकिन राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भाजपा संसदीय प्रतिनिधिमंडल आदि की नींद एकसाथ 2024 में खुली है! अब प्रधानमंत्री मोदी भी 7 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, बंगाल जा रहे हैं, जहां वह महिलाओं की ही जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तमाम अभियान 'राजनीतिक' लगते हैं, क्योंकि सालों तक सभी खामोश और निष्क्रिय थे, लेकिन आज बंगाल में 'राष्ट्रपति शासन' तक की आवाजें मुखर हुई हैं। यहां तक कि जमीनी रपटें सामने आई हैं कि संदेशखाली की औरतों को तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बुलाया जाता था और रात भर उन्हें 'मनोरंजन' के लिए विवश किया जाता था। ऐसे कबूलनामे औरतों ने कैमरे के सामने कहे हैं, हालांकि चेहरे ढक कर वे बोली हैं, क्योंकि उन्हें 'अत्याचारी राक्षसों' का खौफ है। दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि शोषित और पीड़ित औरतों को, खुद को, तृणमूल की समर्थक और वोटर भी कहना पड़ रहा है। औरतों की पारिवारिक बची-खुची जमीनें भी छीन ली गई हैं और अब उन पर तृणमूल कांग्रेस के 'राजनीतिक गुंडों' के अवैध कब्जे हैं। अत्याचार और सामूहिक दुष्कर्म के यथार्थ कई पक्षों ने सामने रखे हैं, लिहाजा उन्हें खारिज करना आसान नहीं है। कमोबेश संवैधानिक पदासीन चेहरों को झूठा करार नहीं दिया जा सकता। उनके भी सामाजिक दायित्व हैं। अब मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। आज सुनवाई में उसका फैसला क्या होगा, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। हमने कहा था कि ममता बनर्जी ने ऐसे हालात पहले देख और अनुभव कर रखे हैं। इस संदर्भ में सिंदुर और नंदीग्राम के आंदोलन याद आते हैं, जो टाटा मोटर्स के प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थे। तब ममता विपक्ष में थीं और आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। तत्कालीन वाममोर्चा सरकार और पार्टी समूह ने ममता पर जो हिंसक और जानलेवा हमले किए थे, उन्होंने बंगाल में 'वाम' के अंत की शुरुआत कर दी थी। आज 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है। ममता भी 'वाम' की तरह घमंडी और एकाधिकारवादी हैं। संदेशखाली में जो विरोध-प्रदर्शन उभरे हैं, उनमें शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सरीखे तृणमूल गुंडों की गिरफ्तारी की मांग गूंज रही है। शेख तब से 'भगोड़ा' है, जब उसके घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा था और हिंसक भीड़ ने जांच अधिकारियों को ही घायल कर दिया था। क्या यह संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जानकारी ही न हो कि उनका 'सिंडिकेट' कहां है? ममता-राज के दौरान तृणमूल के भीतर ही ऐसा सिंडिकेट बना दिया गया है, जो ज्यादातर हिंदू आबादी पर ही दरिंदगी दिखाते हैं। पुरुषों को जान से मार देने की धमकियां भी देते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसी सिंडिकेट ने भाजपा के खिलाफ 273 घटनाएं की थीं। कई कार्यकर्ताओं को भी मार दिया गया था। यह गुंडई पंचायत चुनावों में सरेआम कहर ढहाती रही है। क्या एक महिला मुख्यमंत्री का शासन ऐसा भी हो सकता है कि दरिंदे खुलेआम हत्याएं और अत्याचार कर सकें? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं।

संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां 'दरिंदों' के अत्याचार, यौन उत्पीडऩ और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसएस का अड्डा है और वही औरतों को उकसा और बरगला रहा है। यदि संघ किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आश्चर्य यह भी है कि संदेशखाली की औरतों पर सालों से अत्याचार, अनाचार किए जा रहे थे, लेकिन राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भाजपा संसदीय प्रतिनिधिमंडल आदि की नींद एकसाथ 2024 में खुली है! अब प्रधानमंत्री मोदी भी 7 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, बंगाल जा रहे हैं, जहां वह महिलाओं की ही जनसभा को संबोधित करेंगे।

काले धन की वजह से यह चलता रहा कि पैसा देने वाले राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों से बेजा फायदा उठाते रहे

पॉलिटिकल फंडिंग पारदर्शी, साफ-सुथरी हो

डा. अश्वनी महाजन

राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गई धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है। उन्हें जो पैसा चंदे या दान के रूप में मिलता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराएंगे। पहले जो धन बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से हासिल होता था, उसकी जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन नगदी चंदे के बारे में पारदर्शिता का पूरा अभाव था। यह तो स्थापित तथ्य है कि हमारे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में काले धन की मौजूदगी जमाने से रही है और इस समस्या के समाधान पर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है और उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। पर इस संबंध में जो पहली चीज विचार करने लायक है, वह यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को क्यों लाया गया था? राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गई धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है। उन्हें जो पैसा चंदे या दान के रूप में मिलता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराएंगे। पहले जो धन बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से हासिल होता था, उसकी जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन नगदी चंदे के बारे में पारदर्शिता का पूरा अभाव था। यह तो स्थापित तथ्य है कि हमारे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में काले धन की मौजूदगी जमाने से रही है और इस समस्या के समाधान पर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है। काले धन की वजह से यह चलता रहा कि पैसा देने वाले राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों से बेजा फायदा उठाते रहे। यह स्थिति हमारी राजनीतिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इस पृष्ठभूमि में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाकर यह प्रयास हुआ कि काले धन की समस्या को रोका जाए, उसे हतोत्साहित किया जाए। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है और किसी पार्टी को दिया जा सकता है। एक निर्धारित समयावधि के अंदर पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेती थीं। इस पद्धति में यह सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं था कि किस पार्टी को किस व्यक्ति या संस्था ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया है। इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन-देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है। जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राजनीतिक दल पैसा जुटाते थे, उसमें भी पारदर्शिता का बड़ा अभाव था। साथ ही, यह भी समस्या थी कि जो लोग भारी मात्रा में

नगदी दे रहे हैं, उनके पैसे का स्रोत क्या है, इसका पता लगा पाना असंभव था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा जाए, तो आगे शायद अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में यह तो संभव है नहीं कि धन का कोई एक केंद्रीय संग्रहण हो और सभी दलों को उसमें से एक समान हिस्सा मुहैया कराया जाए। दलों की विचारधारा अलग-अलग है। मान लीजिए कि मुझे चंदा देना है और मैं समझ रहा हूं कि किसी दल की विचारधारा और कार्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित हैं तथा देश के लिए नुकसानदेह हैं, तो मैं उस दल को चंदा नहीं देना चाहूंगा। अगर सभी दलों को एक समान चंदा मिलेगा, तो पार्टी बनाना एक धंधा बन जाएगा। ऐसे में यह व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है कि वह किसी एक दल को चंदा दे या कुछ दलों में अपनी धनराशि को अपनी समझ से बांट दे। यह कई लोगों की समझ है और मैं इससे सहमत हूं कि चुनावी चंदे के मामले में नगदी का चलन नहीं होना चाहिए और चंदा हमेशा ऐसी व्यवस्था के तहत लिया और दिया जाए, जिससे उसके स्रोत के बारे सही जानकारी मिल सके। यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि पारदर्शिता के साथ यह पता चलना चाहिए कि किस दल को किस व्यक्ति या संस्था ने कितनी धनराशि दी है, तो यह कानून की एक व्याख्या है और इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सरकार ने नहीं स्वीकार करते हुए संसद में फिर से कानूनों को पारित किया। साथ ही, ऐसे उदाहरण भी हैं, जब अदालती आदेशों के मुख्य बिंदुओं को स्वीकार करते हुए और कानून में उन्हें समाहित करते हुए संशोधित कानून पारित किए गए। चूंकि अभी सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पढने और उस पर विचार करने के लिए समय चाहिए, इसलिए हमें सरकार के पक्ष को विस्तार से सामने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों के अनुरूप वर्तमान व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, तो वह एक संशोधित प्रारूप संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन यह कार्य अभी तुरंत नहीं हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि देश कोई एक-दो दिन या वर्ष के लिए नहीं होता। राष्ट्र की यात्रा सतत होती है। इस यात्रा में व्यवस्थाएं बनती हैं, बदलती हैं और टूटती भी हैं। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मई में नई लोकसभा और सरकार का गठन हो जाएगा। इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अल्पकालिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो देश और सरकार को उसका सम्मान करना है, लेकिन यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि चुनाव में काले धन का प्रकोप जिस स्तर पर था, उससे निपटने की दिशा में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था एक प्रगतिशील कदम थी। इसी सरकार के कार्यकाल में यह कानून बना था, इसलिए इसी सरकार को यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों और निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक संशोधित व्यवस्था लाई जाए? ऐसा तो अब नहीं हो सकता है कि हम पहले के काले धन वाले समय में लौट जाएं, जहां न तो पैसे के स्रोत का पता चलता था और न ही पैसा देने वाले के बारे में। आज भी हर चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग बड़ी मात्रा में नगदी की धरपकड़ करता है। पहले भी कई बार आयोग की ओर से कहा जा चुका है कि चुनावों में बाहर से पैसा आने के अंदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यवस्था या नियम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन बल का हस्तक्षेप न हो और स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव हों। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धनबल, बाहुबल, जाति आदि अधिक खतरनाक कारक हैं जो खुले तौर पर लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। राजनीतिक फंडिंग से संबंधित कानून में संशोधन करते समय, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों द्वारा नकद प्राप्तियों की पुरानी प्रणाली पर वापस न लौटा जाए, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और यहां तक कि बाहुबल के खेल तथा अवैध धन और अनैतिक गतिविधियों से प्राप्त धन के उपयोग की अनुमति देगी।

दृष्टि कोण

बहुराष्ट्रीयकरण के दौर में जरूरी है मातृभाषा और बोलियों का संरक्षण, तकनीक कर रही है मदद

उदारीकरण के दौर में जब अंग्रेजी अपनी चमक बिखेर रही है, ऐसे में सवाल उठ सकता है कि मातृभाषाओं की जरूरत क्या है? चूंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण की भाषा के रूप में अंग्रेजी अघोषित तौर पर प्रतिनिधित्व हासिल कर चुकी है, इसलिए ऐसा स्वाभाविक भी है। खासकर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दुनिया भर के समाजशास्त्री और बाल मनोविज्ञानी मानते हैं कि शिक्षा हासिल करते वक्त बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा सहज रहता है। इसकी वजह यह है कि मातृभाषाओं का रिश्ता व्यक्ति के दिल से ज्यादा रहता है। दरअसल, दिमाग के जरिये जो कुछ ग्रहण होता है, वह तार्किकता से पूर्ण होता है। तार्किकता मनुष्य के नजरिये को वैज्ञानिक तो बनाती है, पर वह कई बार मर्म को छू नहीं पाती। वहीं दिल से स्नेह और प्यार का रिश्ता है। मातृभाषा को इसी संदर्भ में समझें, तो वह दिमाग नहीं, दिल की भाषा है। मां के दूध में जिस तरह पौष्टिकता के साथ ही स्नेह होता है, मातृभाषाएं भी मनुष्य के लिए स्नेह और पौष्टिकता-दोनों

सहज उपलब्ध करा देती हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर किसी शख्स से आप उस भाषा में बात करते हैं, जो उसकी दूसरी भाषा है, जिसे वह समझ सकता है, तो वह भाषा उसके मस्तिष्क में जाती है। लेकिन अगर आप उसकी मातृभाषा में बात करते हैं, तो वह सीधे उसके दिल तक पहुंच जाती है। यह दिल का रिश्ता ही है कि जब एक भाषा क्षेत्र के लोग मिलते हैं, तो वे अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज महसूस करते हैं। दुनिया ने लोकतंत्र को शासन की बेहतर प्रणाली माना है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्थाएं इसी लोकतांत्रिक समाज में उपजी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उदारीकरण कम से कम भाषाओं के लिहाज से लोकतांत्रिक नहीं हो पाया है। उसकी प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है। अगर उसने किसी अन्य भाषा को इस दिशा में कुछ छूट दी है, तो वह फ्रेंच, स्विस या यूरोप की कुछ ताकतवर समुदायों की भाषाएं ही हैं। लेकिन इनमें भी अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बाजार की बढ़ती ताकत के दौर में उदारीकरण अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं को भी बढ़ावा दे रहा है। पर यह आधी सच्चाई है। अगर उदारीकरण स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहा है, तो वह भाषाओं का लोकतंत्रीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि उनके जरिये अपना ही विस्तार कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि मातृभाषाओं की जरूरत ऐसी ही रहेगी। मातृभाषाएं इसलिए जरूरी हैं, कि शख्स सहज बना रहे। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि मातृभाषा में सहज शिक्षा हासिल कर चुका विद्यार्थी दूसरी भाषाओं को कहीं अधिक प्रवीणता से सीख पाता है। मातृभाषाओं की जरूरत इसलिए भी है कि मानव समाज की विरासत और धरोहर को उन्होंने ही सहेज रखा है। धरोहरों के भाव और संदेश को किसी अन्य भाषा में अनूदित नहीं किया जा सकता। वह अनुवाद दिमागी ही होगा, उसका दिल के मर्म से संबंध नहीं होगा। मातृभाषाओं की जरूरत इसलिए भी है कि वे अभिव्यक्ति की दुनिया को लोकतांत्रिक बनाती हैं, भावों को सहज संप्रेष्य बनाती हैं। इस तरह से वे मानवता की सेवा करती हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की सहज भागीदारी, समावेशी शिक्षा, सामाजिक और प्राकृतिक विविधता के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मातृभाषाएं ही हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा के जरिये जहां प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, वहीं देश की भाषाओं के आंकड़े और बुनियादी उच्चारण आदि का संग्रह भी किया जा रहा है। देश में 1,652 भाषाएं हैं और वे अपने-अपने समाजों की मातृभाषा भी हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर इनका सर्वेक्षण भी कराता रहता है। पिछले साल नवंबर तक मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, जिन्हें संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक वेब संग्रह तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, इस संग्रह में तमाम भाषाओं को रखा जाएगा।

कुछ अलग

घाटे की दुकानदारी

हिमाचल के बजटीय घाटे की दुकानदारी चला रहे सार्वजनिक उपक्रमों ने पुनः लुटिया इस कद्र डुबोई है कि इनके दोष कान खड़े कर रहे हैं। यह सिर्फ घाटा नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता का ऐसा अवांछित रिसाव है, जिसे तुरंत रोकना होगा। कुल 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से तेरह ने 5143 करोड़ का घाटा परोस कर कई ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो पूछ रहे हैं, क्या इसी धरातल पर आत्मनिर्भर हिमाचल की कसम उठाई जाती है। आश्चर्य यह कि जहां संभावना है, वहीं घाटे को सिर पर चढ़ाया जा रहा है। घाटे के शिखर पर परिवहन निगम के 1966 करोड़, राज्य बिजली बोर्ड के 1824 करोड़, पावर कारपोरेशन के 690 करोड़ और ट्रांसमिशन कारपोरेशन के 373 करोड़ बता रहे हैं कि हमारी नीतियां, वित्तीय प्रबंधन और व्यवस्थागत खामियां किस तरह नोच रही हैं। जाहिर है एचआरटीसी को घाटे की आदत इसलिए नहीं पड़ी कि मेहनतकश कर्मचारियों ने कुछ गलत किया, बल्कि सियासी नेतृत्व ने इसकी क्षमता का खैरात समझकर उपयोग किया। परिवहन निगम की सुध लेने के बजाय इसे मरे हुए सांप की तरह किसी न किसी मंत्री के गले में डाल दिया जाता है, जबकि बदले में नए बस डिपो की बढ़ोतरी में कमोबेश हर सरकार ने घाटा बढ़ाया है। इसके मुकाबले निजी बसें कर अदायगी के बावजूद अपने खर्चों के माप तोल को लाभकारी स्थिति में बनाए रखती हैं। दूसरी ओर बिजली बोर्ड व इसके सहायक निगम घाटे का जंजाल इसलिए भी बुन रहे हैं, क्योंकि मुफ्त की बिजली अब ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की हैसियत को दुबला ही करेगी। हैरान तो पर्यटन विकास निगम का 127 करोड़ का घाटा भी कर रहा है। जिस क्षेत्र के माध्यम से हिमाचल आत्मनिर्भर होने की सौगंध खाता रहा है, उसके बाजुओं पर विराजित सरकारी निगम की ऐसी दयनीय हालत का गुण-दोष निकालते हुए कब तक सरकारी होटलों का विनिवेश होता रहेगा। सरकारी क्षेत्र के पास बेहतरीन साइटस, संपत्तियां और विश्वसनीय के बावजूद अगर घाटा है, तो यह घपला है। घाटे में घपले के किरदार को पकडऩे के बजाय नित नई संपत्तियां ऐसी जगह जोड़ी जा रही हैं, जहां कायदे से इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए नूरपुर में दो बार सरकारी निवेश से पर्यटन निगम की इकाइयां अगर शून्य हुईं, तो इसकी वजह नालायकी व सियासी सोच है। धर्मशाला में क्रिकेट व अन्य कारणों से होटलों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के अनुरूप खुद को सशक्त किया, जबकि इसके मुकाबले टूरिज्म कारपोरेशन की चार संपत्तियां खुद को परिमार्जित ही नहीं कर पाईं। विडंबना यह है कि मिल्क फेडरेशन सत्रह करोड़ का घाटा उठा कर भी उपभोक्ताओं की मांग का सामना नहीं कर पा रही। पड़ोसी राज्यों के दुग्ध उत्पाद अगर हिमाचल न आएं, तो हमारी चाय और कड़वी हो जाएगी, लेकिन हिमाचल मिल्क फेड आज तक वेरका, वीटा या मदर डेयरी से उपभोक्ता जरूरत को समझ नहीं पाया। यह दीगर है कि सरकार दूध खरीद तथा डेयरी उत्थान की घोषणा में वर्तमान बजट का आश्वासन दे रही है, फिर भी यह सोचना होगा कि मिल्क फेड जैसे सार्वजनिक उपक्रम क्यों अपनी गुणवत्ता से उपभोक्ता जरूरतों का लाभकारी बाजार खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल में घाटे के वही उपक्रम हैं, जिनके जरिए राज्य के संकल्प तथा आत्मनिर्भरता के कदम मुकम्मल होंगे। ऐसे में निजी निवेश ही एक मात्र सहारा बचता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, सेवा क्षेत्रों तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में निजी निवेश को अगर प्रेरित-प्रोत्साहित किया जाए, तो कहीं अधिक आय के संसाधन पैदा होंगे। घाटे की व्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों में धन व्यर्थ करने से कहीं अच्छा होगा कि इनमें से अधिकांश का विनिवेश किया जाए या मौजूदा प्रबंधन प्रणाली का व्यावसायीकरण करते हुए इन्हें राजनीतिक प्राथमिकताओं का खिलौना न बनाया जाए।

देश दुनीया से

अली खड्ड विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो

प्रशासन अपनी जिद पूरी करने के लिए मुद्दे की बात समझने के बजाय आंदोलन को लंबा लटका कर लोगों को थका कर आंदोलन को समाप्त करने की रणनीति अपनाने का प्रयास करता है। यह समस्या को बिना सुने-समझे टाल देने का तरीका वाजिब नहीं है। यदि प्रशासन की बात सही है तो तर्क और पूरी सूचना देकर मामला सुलझाया जा सकता है। और यदि आंदोलनकारियों की बात तथ्यात्मक है तो तथ्यों का ध्यान रखते हुए मामला हल किया जा सकता है। जीवनयापन के लिए अपरिहार्य रूप से आवश्यक संसाधनों की जब बात आती है तो स्थनीय निवासियों के अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय की मांग है। जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह सही हों, तो किसी एक की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने चाहिए।

भारत वर्ष में विकास के मेगा प्रोजेक्ट और स्थानीय हितों में टकराव के समाचार रोज कहीं न कहीं से आते ही रहते हैं। यह ठीक है कि कुछ नया बनेगा तो कुछ पुराने को हानि भी झेलनी पड़ेगी, किन्तु जीवन के लिए आवश्यक हवा, पानी और भोजन जैसे संसाधनों पर जब चोट पडऩे लगती है तो मामला चिंतनीय हो जाता है, जिस पर तार्किक रूप से विचार करना जरूरी हो जाता है। किन्तु खेद का विषय है कि आम तौर पर स्थानीय निवासियों के हितों पर परियोजना हितों को वरीयता दी जाती है। इस स्थिति में टकराव शुरू हो जाते हैं, जिनका परिहार यदि तर्क और स्थानीय हितों को ध्यान में रख कर न किया जाए तो मामले बिना वजह ही उलझ जाते हैं और बहुत बार अनावश्यक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं। कई बार गलत या अधूरी सूचनाओं के कारण भी मामले उलझ जाते हैं। आजकल बिलासपुर जिला में इसी तरह का आंदोलन अली खड्ड के पानी को लेकर चल रहा है। आंदोलनकारी तीन सप्ताह से बैठे हैं, किन्तु किसी अर्थपूर्ण संवाद के अभाव में कोई हल निकल नहीं सका है। अनुभव यह बताता है कि शांतिपूर्ण आंदोलनों को जब समय पर सुना नहीं जाता है तो आंदोलन उलझ जाते हैं और कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं। इसलिए एक स्वस्थ प्रजातंत्र में लोगों के असहमति के अधिकार का सम्मान करते हुए आंदोलन की बात को जल्दी सुना जाना चाहिए। किन्तु प्रशासन अपनी जिद पूरी करने के लिए मुद्दे की बात समझने के बजाय आंदोलन को लंबा लटका कर लोगों को थका कर आंदोलन को समाप्त करने की रणनीति अपनाने का प्रयास करता है। यह समस्या को बिना सुने-समझे टाल देने का तरीका वाजिब नहीं है। यदि प्रशासन की बात सही है तो तर्क और पूरी सूचना देकर मामला सुलझाया जा सकता है। और यदि आंदोलनकारियों की बात तथ्यात्मक है तो तथ्यों का ध्यान रखते हुए मामला हल किया जा सकता है। जीवनयापन के लिए अपरिहार्य रूप से आवश्यक संसाधनों की जब बात आती है तो स्थनीय निवासियों के अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय की मांग है। जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह सही हों, तो किसी एक की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने चाहिए। इस प्रक्रिया में दलगत राजनीतिक हित साधने के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो अली खड्ड आंदोलन में दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता एक स्वर में त्रिवेणी घाट से पानी उठाकर अंबुजा सीमेंट प्लांट को देने का विरोध कर रहे हैं। विरोध का तार्किक आधार यह है कि जहां से पानी उठाया जा रहा है, वहां से नीचे बिलासपुर जिला के चार निर्वाचन क्षेत्रों को पानी अली खड्ड से मिल रहा है जिसके लिए 24 लिफ्ट और ग्रेविटी पेयजल योजनाएं, 7 सिंचाई लिफ्ट योजनाएं, स्थानीय कूहलें और घराट तथा मछली प्रजनन केंद्र चल रहे हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा जनसंख्या की पानी की जरूरतें पूरी हो रही हैं। 1992 में भी यह योजना गुजरात अंबुजा के पूर्व मालिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी जिसे वीरभद्र सिंह सरकार ने डाउन स्ट्रीम स्थानीय समुदाय का पक्ष सुन कर रद्द कर दिया था। अब नए मालिक ने फिर से

उस योजना को पुनर्जीवित करके निर्माण कार्य शुरू करवाया है, भले ही इसके लिए जलशक्ति विभाग को माध्यम बनाया गया है। बिलासपुर जिला की 50 से अधिक पंचायतों के लाभार्थी इस योजना के विरोध में त्रिवेणी घाट पर तीन सप्ताह से ज्यादा दिनों से धरना दे रहे हैं। गत 13 फरवरी को एक्शन कमेटी द्वारा त्रिवेणी घाट पर लाभार्थियों द्वारा महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय भाजपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। इसमें अन्य समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। महा पंचायत समाप्त होने के बाद भीड़ निर्माण स्थल में घुस गई और सोलन पुलिस से टकराव हो गया। निर्माण कार्य को भी क्षति हुई और कुछ लोगों को चोटें भी आईं, जो हिमाचल के शांतिपूर्ण माहौल के लिए चिंता की बात है, जिसकी निंदा करना भी जरूरी है। आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज किए गए जिसमें जो लोग मौका से दो घंटे पहले ही जा चुके थे, उनके नाम भी एफआईआर दर्ज हो गई है। इस तरह मामले उलझते हैं, सुलझते नहीं। असल में इस अली खड्ड का पानी डाउन स्ट्रीम आबादी की आवश्यकताओं के लिए भी गर्मियों में कम पड़ जाता है और टैंकर लगा कर लोगों की प्यास बुझानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में इस नाले पर नया बोझ डालना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता। स्थानीय लोगों की चिंताएं वाजिब हैं।

आप का नजरीया

अब सत्य युग आने की बारी...

धरती पर समय को चार युगों के क्रम में बांटा गया है- सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। सबसे पहले सत्य युग या सद्युग, फिर त्रेता, तब द्वापर, अंत में कलि युग आता है। पुराणों में इसका वर्णन है।

"सत्य युग, द्वापर त्रेता मध्ये..."

कहते हैं- सत्य युग में धर्म के चारों पाए या स्तम्भ सशक्त रहते हैं (यहाँ पर धर्म का अर्थ यह नहीं होता कि वे किस देवता की पूजा करते हैं या किस मसीहा को मानते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य या उत्तरदायित्व से है। जैसे राज-धर्म का अर्थ है- राजा के कर्तव्य, पुत्र-धर्म का अर्थ है- पुत्र के कर्तव्य, पति-धर्म का अर्थ है- पति के कर्तव्य और पत्नी-धर्म का अर्थ है- पत्नी के कर्तव्य।) इस युग में ज्ञान, ध्यान या तपस्या की प्रधानता होती है। यह सत्य तथा न्याय का युग कहलाता है। सर्वत्र पुण्य-काल का अर्थ यही सत्य युग है। सत्य युग बीत जाने के बाद त्रेता की बारी आती है। कहते हैं- त्रेता युग में धर्म का एक पाया टूट जाता है। यानी इस युग में पाप और झूठ-फरेब का आरम्भ होता है और सत्य, न्याय की अंशतः हानि होती है, पर धर्म तीन पायों पर टिका रहता है। इसी प्रकार, द्वापर युग में धर्म के दो पाये टूट जाते हैं और पाप का विस्तार होकर सत्य, न्याय की बहुत हानि होती है, इसका आधा हिस्सा पाप में घिर जाता है। धर्म दो स्तंभों के सहारे ही टिका रहता है। कलि युग में धर्म के तीन पाये टूट जाते हैं और यह एक पाये पर किसी तरह से लड़खड़ाता टिका रहता है। सत्य, न्याय की बहुत अधिक हानि होती है और पाप, झूठ-फरेब और अन्याय अपने चरम पर होते हैं। तीन युग बारी-बारी से आये और गए। अब कलि युग चल रहा है। पाप और अन्याय का अँधेरा हर ओर से धरती को ढंके हुए है। ऐसे में महामारी, भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा, वज्रपात, भू-स्खलन, बादल फटना, दुर्घटनाएं जैसी प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही जो पूरी जनसंख्या को एक बार में समाप्त कर सकती हैं। लेकिन 25% लोग जो इस भयानक अँधेरे में भी न्याय, विवेक और ईमानदारी का प्रकाश-दीप हाथ में पकड़ कर सत्य के मार्ग पर चलते जा रहे हैं, वही धर्म-रक्षक हैं और उन्हीं के सहारे इस घोर कलि युग में भी धरती और प्रकृति धीरज धारण कर अनवरत चल रही है। ऐसा नहीं कि इन ईमानदार लोगों को कलि युग कोई कष्ट नहीं देता। कलि युग तो अपनी सत्ता के समय में इन विद्रोहियों को ढूंढता रहता है और बहुत कष्ट भी देता है। पर ये धर्म-रक्षक ईश्वर का ध्यान कर, ध्यान-ज्ञान-विज्ञान का हाथ थामकर कलि युग की सत्ता को समझते हुए सब कुछ सहन कर अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं। इन्हें प्रतीक्षा है कि समय का चक्र अपनी गति से घूमेगा और कलि काल के समाप्त होने पर फिर सत्य युग आएगा। यहाँ यह गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि कलियुग के बाद त्रेता या द्वापर आता है। कई लोग पूरी दुनिया में चारों ओर अन्याय, झूठ-फरेब और पाप का बोलबाला देखकर हैरान हैं, कई सम्प्रदाय के लोग इस बात से बहुत दुखी और भयंकर गुस्से में हैं कि उनके अपने सम्प्रदाय के लोग ही उनकी निंदा कर उन्हें नीचा दिखा रहे हैं।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री बोले

पिछली कांग्रेस सरकार ने ईआरसीएपी को अटकाने और भटकाने का किया काम

जयपुर (हिंस)। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले दो दशक से ज्यादा समय से जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन विषयों पर सहमति बन पाई। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर कांग्रेस सरकार ने लोगों के प्यासे कंटों पर राजनीति करते हुए इस परियोजना को अटकाने और भटकाने का काम किया। गुरुवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके दिए हुए सुझावों के तहत नदी जोड़ने की परियोजना को लेकर दो राज्यों में सहमति बनाने में सफलता मिली। यह समझौता दो राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे या दो राज्यों के बीच नदी जोड़ने का समझौता मात्र नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के

पूर्ववर्ती 13 जिले, अब 21 हो गए हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिलों के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों को व राजस्थान से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही राजस्थान में 30 जिलों को तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएगी। शेखावत ने कहा, ठीक इसी तरह शेखावाटी के तीनों जिलों में पेयजल संकट बना हुआ है। हरियाणा पानी की मंजूरी नहीं देने पर अड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के सुझावों के आधार पर यह स्वीकृति प्रदान की। शेखावत ने कहा, दोनों योजनाओं की फाइनल डीपीआर पर तेज गति से काम शुरू हो गया है और दोनों योजनाओं को सीमित समय दिया गया है कि डीपीआर बने और कैबिनेट में अप्रूवल करवाकर काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश के 13 और राजस्थान के 21 जिलों के साथ ही पूरे राजस्थान को सुचारू पानी पहुंचाने का है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 25 को

जयपुर (हिंस)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 25 फरवरी, रविवार को सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2023 (सांख्यिकी विभाग) का आयोजन जयपुर शहर के 41 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दोपहर 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 23 फरवरी एवं 24 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं 25 फरवरी की सुबह 8 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षा नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के आयोजन के लिए पुलिस, यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

योगी आदित्यनाथ बहुत ही डायनमिक मुख्यमंत्री : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

गोरखपुर (हिंस)। आयकर विभाग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हर गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही डायनमिक मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के लिए डायनमिक शब्द को समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 जिले हैं और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। योगी आदित्यनाथ साल भर में प्रत्येक जिले का कम से कम एक बार दौरा जरूर कर लेते हैं। कुछ जिलों में यह संख्या और कई बार होती है। वह इंजन की तरह प्रदेश में घूमते रहते हैं। हर जिला ही उनके लिए हेडक्वार्टर है। प्रथम बार गोरखपुर आगमन को लेकर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन और मुझे गोरखपुर इतना सुंदर लगा जितना सोचा भी नहीं था। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व सरकार बार बार यह साबित कर रही है कि जिसका शिलान्यास होगा, उसका उद्घाटन भी होगा। सभी परियोजनाओं के पूरा होने की गारंटी ही मोदी जी की गारंटी है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की चार प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने बताया कि गोरखपुर के खाद कारखाना और एम्स का शिलान्यास जुलाई 2016 में किया गया और दिसंबर 2021 में इन सभी का लोकार्पण भी हुआ। गोरखपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रीजनल सेंटर का 2018 में शिलान्यास हुआ तो दिसंबर 2021 में उद्घाटन भी। 1978 से लंबित सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने किया। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों के 6200 गांवों में रहने वाले 29 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रही है। इस परियोजना के शुरू हो जाने से 14 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन आसान हुआ है। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए कहा कि सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.77 प्रतिशत बड़ा है। इसके साथ ही अप्रैल 2023 से 10 जनवरी 2024 तक 2.48 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड भी किया गया है। साठ-सत्तर के दशक से वर्ष 2009 तक पुराने टैक्स क्लेम के मामलों में 25 हजार रुपए की धनराशि पर राहत प्रदान की गई है। फेसलेस सिस्टम के चलते शिकायतों में 60 प्रतिशत कमी आई है। आयकर विभाग प्रतिदिन 1.66 करोड़ असेसमेंट कर लेता है जबकि एक सप्ताह में 3.43 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है।

महिला शिक्षक ने लगाए व्याख्याता पर प्रताड़ित करने के आरोप

झुंझुनू (हिंस)। झुंझुनू डाइट में कार्यरत लेक्चरर पर एक महिला शिक्षिका से फोन पर गलत बातें व मैसेज करने के आरोप लगाए। आरोप मुकुन्दगढ़ (झुंझुनू) की सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका ने लगाए हैं। शिक्षा मंत्री व कलेक्टर से लिखित में शिकायत की गई है। महिला टीचर ने शिकायत में लिखा है कि डाइट लेक्चरर परमेंद्र कुल्हार पर लगातार प्रताड़ित कर रहा है। जब मैं बुडाना में लेक्चरर के पद पर थी तब परमेन्द्र फोन व मैसेज कर गलत बातें करने की कोशिश करता था। उसे ऐसा न करने के लिए धमकाया तो वह प्रताड़ित करने लगा है। टीचर ने लिखा है कि जब परमेंद्र समसा में पीओ के रूप में कार्यरत था, तब निरीक्षण के बहाने मेरे स्कूल आया। मैं नहीं मिली तो स्टाफ के सामने मेरे बारे में गलत बातें कही। शिकायत में लिखा कि एक दिन परमेंद्र मेरे घर तक पहुंच गया और एपीओ कराने की धमकी दी। 6 फरवरी 2024 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से उप निदेशक उर्मिला चैधरी को साथ लेकर वह मेरे स्कूल आ गया। वहां 3 घंटे तक मुझे व अन्य टीचर्स को विद्यार्थियों के सामने डांट-फटकार लगाई। अपमानित किया और एपीओ या सस्पेंड करवाने की धमकी दी। मैं और मेरा स्टाफ स्कूल में समय पर आते हैं। विद्यालय में कैमरे लगे हैं। इसके बावजूद उर्मिला चैधरी व परमेंद्र ने विजिट रजिस्टर में जान-बूझकर लिखा कि टीचर्स लेट आते हैं। जबकि ऐसा कोई सबूत भी नहीं था। शिकायत में लिखा कि जब भी उर्मिला चैधरी आती हैं तो डाइट लेक्चरर परमेंद्र अनाधिकृत रूप से दो दिन दौरे पर रहता है।

किसान आंदोलन के चलते रास्ते बंद होने से उद्योगों को होगा अरबों का नुकसान

झज्जर (हिंस)। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा टीकरी बॉर्डर बंद किए हुए गुरुवार को 10 दिन हो गए। इससे बहादुरगढ़ में दूसरे लोगों के अलावा उद्यमियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्योगों के कच्चे और तैयार माल की ढुलाई सुविधा के साथ नहीं हो पा रही। उद्यमियों का कहना है कि इस बार आंदोलनकारियों ने टीकरी बॉर्डर के साथ बहादुरगढ़ में डेरा डाल लिया तो न केवल उद्योगों को भारी नुकसान होगा, बल्कि लाखों कामगारों का रोजगार भी चला जाएगा। कॉनफेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्यमियों ने कर्मचारियों के साथ पंडित श्रीराम मेट्रो स्टेशन लेकर टिकरी बार्डर तक शांति मार्च निकाला। इस मार्च के माध्यम से कर्मचारियों ने किसानों से बहादुरगढ़ को आंदोलन का केंद्र न बनाने की अपील की। कोबी प्रधान व उद्यमी प्रवीन गर्ग ने कहा कि किसान संगठन जल्द

से जल्द इस आंदोलन का समाधान निकाले, ताकि उद्योग धंधे प्रभावित न हो। प्रवीन गर्ग व कई अन्य उद्यमियों ने बताया कि आंदोलन के कारण सेक्टर-9 और टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। जिसके कारण न तो माल आ रहा है और न ही जा पा रहा। जिसके चलते उद्यमियों की परेशानी बढ़ी हुई है। झज्जर जिले में करीब आठ हजार औद्योगिक इकाईयां चल रही हैं, जिसमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा बहादुरगढ़ में हैं। पहले कोरोना महामारी के कारण उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान से उद्यमी उभरे भी नहीं थे कि 2021 में किसान आंदोलन के कारण एक साल से ज्यादा समय तक टिकरी बॉर्डर बंद रहा। जिसके कारण उद्यमी ही नहीं बल्कि आमजन को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटी इकाईयां यह मार सह नहीं पाई बंद हो गई। न जाने कितने कर्मचारियों को इस वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब फिर वहीं हालात बन गए है। ऐसे में सभी उद्यमी यह अपील करते है कि 2021 वाली स्थिति उत्पन्न न हो। जिसके कारण लाखों कर्मचारियों को अपने रोजगार और उद्यमियों को अपने कारोबार से हाथ धोना पड़े।

बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

पटना (हिंस)। बिहार विधानसभा में गुरुवार को बजट सत्र के 7वें दिन भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को लेकर सदन के अंदर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन के बाहर वाम दलों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा है कि सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाएंगे। ऐसे में उन्होंने यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया और इसी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा सत्र के सातवें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सदन के पटल पर एक सूचना रखते हैं, उसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें कहा कि क्या सूचना है आप बताएं। चंद्रशेखर ने कहा कि सीएम साहब ने कल ही निर्देश दिया था कि सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनकी सूचना सुन स्पीकर ने कहा कि यह मामला शून्य काल में उठेगा और उसे सुना जाएगा। अभी प्रश्न काल चल रहा है और अभी उसी से संबंधित सवाल लिया जाएगा। अपनी सूचना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होते देखा विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि आप लोग अपनी जगह पर जाइए, वेल से कही गई कोई भी बात प्रोसिडिंग का हिस्सा नहीं होती है, यह बात आप भी जानते हैं इसलिए अपनी जगह पर जाइए और शून्य काल के दौरान इस सवाल को उठाइए। हंगामा बढ़ता देख मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में जो घोषणा की है उसे सरकार सुनिश्चित कराएगी, आप लोग इस बात के लिए निश्चित रहें।

हरियाणा सरकार ने अब तक एचएसएसए से 42 हजार लोगों को दीं नौकरियां : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (हिंस)। राज्य में भाजपा सरकार अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान एचपीएससी के माध्यम से 2904 तथा एचएसएसए के माध्यम से 42 हजार 445 युवाओं को नौकरियां दे चुकी है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने सितंबर 2019 से आज तक राज्य में हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से दी गई नौकरियों पर सरकार से रिपोर्ट मांगी। विपक्षी विधायक ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी गई वर्षवार नौकरियों पर भी सरकार से सदन में रिपोर्ट मांगी। विधायक जगबीर मलिक के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर सिंह ने बताया कि एचपीएससी के माध्यम से एक सितंबर 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक 2038 सामान्य श्रेणी, 385 एससी, 214 बीसी ए, 119 बीसी बी, 108 ईडब्ल्यूएस, 26 ईएसएम, चार डीईएसएम, 10 ईबीपी श्रेणी के युवाओं को नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एचपीएससी के माध्यम से वर्ष 2019-2020 में 503, वर्ष 2020-2021 में 284, 2021-2022 में 55, 2022-2023 में 788 तथा 2023-फरवरी 2024 तक 1274 अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गई। मुख्यमंत्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 42 हजार 445 युवाओं को नौकरियां दी गई। जिसमें सामान्य श्रेणी के 15097, एससी श्रेणी के 7108, बीसीए के 5477, बीसीबी के 3395, ईडब्ल्यूएस के 4042, ईएसएम सामान्य श्रेणी में 3299, ईएसएम एससी के 957, ईएसएम बीसीए के 957, ईएसएम बीसीबी के 1317, ईएसपी सामान्य श्रेणी में 277, ईएसपी एससी में 226, बीसीए में 189 तथा बीसीबी में 104 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी आज रिपोर्ट जारी की। एचकेआरएन के मुद्दे पर हरियाणा के विपक्षी दलों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष एचकेआरएन के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लगातार खारिज कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 में एचकेआरएन की स्थापना की। जिसके चलते अब तक 13 हजार 133 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा एक लाख पांच हजार 747 युवाओं को ठेकेदारों की श्रेणी निकालकर एचकेआरएन में जोड़ा गया है।

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनना लोकतंत्र की जीत : विरेंद्र नरवाल

हिसार (हिंस)। आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष विरेन्द्र नरवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हुई मतगणना में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया है। गुरुवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण ने भाजपा को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। विरेन्द्र नरवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द करके अपनी निगरानी में मतगणना करवाकर भाजपा को सच्चाई का आइना दिखाया है। इससे यह साबित हो गया है कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी 36 बिरादरियों के हक की आवाज उठा रही है और इसी के चलते दो बार दिल्ली और अब पंजाब में आआपा की सरकार बन चुकी है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भी अब आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम फहरा दिया है। विरेन्द्र नरवाल ने कहा कि जनता ने देख लिया कि भाजपा ने किस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया था। भाजपा को अपने किए की सजा मिल गई और अदालत में आम आदमी पार्टी की जीत हुई।

कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया ड्रोन, आईईडी बरामद

कठुआ (हिंस)। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन से घुसपैठ की गई। सीमा पर तैनात जवानों की गोलीबारी के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गया। इलाके में चलाया जा रहा तलाशी अभियान जारी है। इस दौरान ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ है। जांच करने पर पैकेट में आईईडी पाई गई। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ जवानों ने हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मनियारी पोस्ट पर एक पाकिस्तानी ड्रोन की आवाजाही देखी। इसके बाद ड्रोन पर फायरिंग की गई।

मंत्रिमंडल बैठक : पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से, जंगी जागीर की राशि की दो गुनी

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा सदन में बजट पेश करेंगे। सरकार ने पंजाब होमगार्ड के बलिदानी वालंटियर जसपाल सिंह के परिवार को एक्स-ग्रेशिया ग्रांट देने, *दा ईस्ट पंजाब वॉर एवॉर्ड्स एक्ट- 1948* का संशोधित बिल पेश करने और राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के *एमएसएमई पंजाब* बनाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बजट सत्र के प्रोग्राम के अनुसार सेशन 1 मार्च को राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद में दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा 5 मार्च को वर्ष 2024-25 के बजट पेश करेंगे। यह सत्र 15 मार्च को सदन अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सुल्तानपुर लोधी में अमन-कानून की रक्षा के दौरान बलिदान हुए जिला कपूरथला के गांव मनियाला के पंजाब होमगार्ड के वालंटियर जसपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह (नंबर- 28475) के योगदान के मद्देनजर बलिदानी के परिवार को विशेष केस के तौर पर एक्स-ग्रेशिया ग्रांट देने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग के डिजाइन विंग को सरकारी स्वामित्व वाले, सहायता प्राप्त कालेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों व संस्थाओं के स्टाफ की तर्ज पर निजी संस्थाओं को डिजाइन और कंसलटेंसी सेवाएं देने को भी मंजूरी दे दी है। इसमें यह शर्त होगी कि डिजाइन और कंसलटेंसी सेवाओं से आने वाले राजस्व का 40 प्रतिशत राज्य के खजाने में जमा करवाया जाएगा। मान मंत्रिमंडल ने *दा ईस्ट पंजाब वॉर ऐवॉर्ड्स, एक्ट-1948* में संशोधन करने के लिए एक बिल विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है।

भारतीय किसान यूनियन ने हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर लगाया जाम

कैथल (हिंस)। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तितरम मोड़ के पास जाम लगाकर धरना दिया। जाम के लिए पर्याप्त संख्या में किसानों के न पहुंचने पर किसानों ने सड़क पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके रास्ता रोक दिया। चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान महाबीर चहल नरड़ के नेतृत्व प्रदर्शनकारियों के पास चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तितरम मोड़ के पास जाम लगा दिया। इससे हिसार, रोहतक और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान नरड़ ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को रोक कर किसानों पर धक्काशाही कर रही है। नरड़ ने कहा कि सरकार की यह धक्केशाही नहीं चलेगी। किसान दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। दरअसल, भाकियू चढ़ूनी गुट ने बुधवार की रात को

पूरे प्रदेश में दोपहर 12 से दो बजे तक रोड जाम करने का आह्वान किया था। इसी घोषणा के अनुरूप गुरुवार को किसानों ने हिसार-चंडीगढ़ मार्ग पर तितरम मोड़ पर जाम लगाया। बीके यूके युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री कैथल आएंगे। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की कैथल में होने वाली मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अगर सभी की सहमति होती है तो 24 फरवरी को कैथल में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा।

उट और गाइड के चिंतन दिवस पर हुआ मंथन

अररिया (हिंस)। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड की ओर से फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग के जन्मदाता की जयंती चिंतन दिवस के रूप मेंगुरुवार को मनाया गया। जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) बैजनाथ प्रसाद व जिला संगठन आयुक्त (गाइड) जूही मल्लिक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद स्थाई समिति के सदस्य इस्लाम अंसारी मौजूद रहे। चिंतन दिवस के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के ध्वज को फहराकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई और संगठन के जन्मदाता वेडन पावेल व उनकी पत्नी के तैलीय चित्र पर स्काउट गाइड व पदाधिकारी के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। चिंतन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए पार्षद मो. इस्लाम ने कहा कि स्काउट गाइड का प्रशिक्षण बच्चों के लिए काफी लाभकारी है। जहां बच्चों में प्रशिक्षण से मानसिक और शारीरिक स्फूर्ति आती है वही बच्चे समाज के प्रति भी काफी संवेदनशील हो जाते है। जिला संगठन आयुक्त बैजनाथ प्रसाद साह ने कहा कि स्काउटिंग गाइडिंग के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 को हुआ था और उनकी पत्नी मिसेज ऑलेव सेंट क्लेयर बेडेन पॉवेल का जन्म 22 फरवरी 1889 को हुआ था । पति एवं पत्नी दोनों के जन्म दिवस 22 फरवरी के संयोग को स्काउटिंग में चिंतन दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष चिंतन दिवस का थीम हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। पर्यावरण और वैश्विक गरीबी हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत स्काउटर राशिद जुनैद ने बताया कि स्काउटिंग की स्थापना 1907 ई. में इंग्लैंड में हुई थी, जो अब विश्व के 216 से अधिक देशों में एक नियम और प्रतिज्ञा के साथ कार्य कर रहा है। इस तरीके से स्काउट गाइड युवाओं का विश्व स्तरीय सबसे बड़ा संगठन है। जिसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं में सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय भावना जागृत कर राष्ट्र के विकास हेतु तैयार करना है। मौके पर स्काउट मास्टर शाहिद आलम, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अमन राय के साथ प्रेम कुमार, सब्दूल, अंश, विशाल, कृष्णा, अजय, मिथिलेश, सूरज, निशा कुमारी, मौसम, सिम्पी कुमारी, सिमरन कुमारी, कुशुम, नुरेशा, कोमल, रिया के साथ दर्जनों स्काउट गाइड उपस्थित थे।

मरू महोत्सव : जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर से निकली शोभायात्रा

जैसलमेर (हिंस)। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर में मरू महोत्सव के तीन दिवसीय आयोजनों की शुरुआत गुरुवार को भव्य शोभायात्रा के साथ हुई। चौबीस फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में सांस्कृतिक और संगीत के कार्यक्रमों की धूम रहेगी। शहर के सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य भगवान लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में सुबह आरती के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ स्थानीय जनता का उत्साह देखने लायक था जैसलमेर में गुरुवार से आयोज्य होने वाले मरू महोत्सव 2024 के कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य भगवान लक्ष्मीनाथजी के मंदिर में आरती के साथ हुई। बाद में गड़ीसर झील से शोभायात्रा सोनार दुर्ग व शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूनमसिंह स्टेडियम तक पहुंची। स्टेडियम में महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने के बाद दोपहर से विदेशी पर्यटकों एवं भारतीयों के लिए साफा बांधो प्रतियोगिता, मूमल महेन्द्रा, मूंछ प्रतियोगिता, मिस मूमल, मिसेज डेजर्ट और

मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सुरमई सांझ पूनमसिंह स्टेडियम मेंआइकन्स ऑफ जैसलमेर के सम्मान के तहत पद्मश्री अनवर खान बईया और पेपे खान को सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात संस ऑफ द सोइल्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पदमश्री अनवर खान बईया, पेपे खान व मेरे राम आएंगे फेम स्वाति मिश्रा प्रस्तुतियां देंगे। स्थानीय बॉलीवुड सेलिब्रिटी बैंड की ओर से भी प्रस्तुति दी जाएगी। मरु महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को गड़ीसर सरोवर से पूनमसिंह स्टेडियम तक निकली मनोहारी शोभायात्रा ने जैसलमेर के बाशिन्दों से लेकर देशी-विदेशी पर्यटकों को मरु लोक संस्कृति से रूबरू कराया। मुख्य बाजार से होती हुई निकली शोभायात्रा का नगर वासियों ने अपने घरों की छतों पर बैठ कर पुष्प वर्षा कर हार्दिक स्वागत किया एवं महोत्सव को उत्सव के रूप में लिया। शोभायात्रा की झलक पाने मार्ग के दोनों तरफ तथा भवनों की छतों पर सैलाब उमड़ पड़ा। बीएसएफ के सजे-धजे ऊंट व इन पर सवार बीएसएफ के जांबाज, केमल माउण्टेन बैंड वादकों का समूह, मंगलकलश लिए बालिकाएं, लोक कलाकारों का कारवां दुर्ग से निकल कर मुख्य मार्ग से होता हुआ शहीद पूनमसिंह स्टेडियम पहुंच कर शानदार समारोह में परिवर्तित हुआ। शोभायात्रा का सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र सीमा सुरक्षा बल के उपसमादेष्टा मनोहर सिंह शेखावत के नेतृत्व में शाही पोषाक में अपने हाथों में भाले लिए हुए बांके जवान, सजे-धजे ऊंटों पर सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहे एवं देशी-विदेशी सैलानियों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया। शोभायात्रा में श्रृंगारित ऊंटों पर सवार रौबीले मरु श्री एवं इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी, मिस ऊंटों एवं ऊंट गाड़ों पर सवार पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित मिस मूमल एवं महेन्दा के प्रतियोगी और विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। लोक कलाकारों के कई जत्थों ने रास्ते भर लोक नृत्यों और लोक वाद्यों से लय-ताल की धूम मचाते हुए मरु संस्कृति और राजस्थानी परंपराओं का दिग्दर्शन कराया। इस बार विदेशी पर्यटकों की अच्छी भागीदारी रही। शोभायात्रा में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए एवं शोभायात्रा के सभी मनोहारी दृश्यों को अपनी चिरस्थायी याद के लिए कैमरो में कैद किया।

शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को सातवां समन, बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी

नई दिल्ली।
ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सातवां समन भेज दिया है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी छह समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सीएम किसी ना किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब सातवां समन जारी होने से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है।

छह समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल

दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले बीती 14 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल छठे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।

केजरीवाल ने कही थी ये बात

छठा समन जारी होने पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं और ईडी को नया समन जारी करने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने से छूट दे दी थी। वहीं ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार बचकाने कारण बता रहे हैं। ईडी ने कहा कि अगर उच्च पद पर बैठे लोग भी इस तरह से कानून का उल्लंघन करेंगे तो इससे आम आदमी के बीच गलत संदेश जाएगा।

क्या हैं आरोप

आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

न्यूज ब्रीफ

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए, कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में दूसरे सीआईआई इंडिया-यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित रखने पर जोर दिया। मंत्री गोयल ने समारोह में कहा, हमारा मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते या द्विपक्षीय समझौते निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित होने चाहिए। दुनियाभर के देशों को यह पहचानने की जरूरत है कि तेजी से बढ़ते देश के रूप में भारत 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। जी20 की अध्यक्षता का किया जिक्र केंद्रीय मंत्री ने भारत के जी20 की अध्यक्षता के पिछले वर्ष को एक सफल वर्ष के रूप में भी बताया। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस और भारत मध्य-पूर्व आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) दोनों के शुभारंभ का भी जिक्र किया। मंत्री गोयल ने कहा कि ये दोनों पारदर्शी माध्यम से दुनियाभर में वृद्धि, विकास और निष्पक्ष व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करेंगे। लैंगिक समानता पर दिया जोर गोयल ने समावेशिता और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, देश न केवल महिलाओं के विकास की दिशा में बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में भी काम कर रहा है। जैसा कि हम सामूहिक रूप से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विस्तार की दिशा में काम करते हैं, हमारा मानना है कि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और युवा प्रतिभाओं के एक बड़े आकांक्षी समूह के साथ भारत तेजी से विस्तार करना जारी रखेगा। मंत्री ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की प्रचुरता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, चाहे वह आधुनिक तकनीक हो, स्थिरता हो, आरई हो, या चक्रीय अर्थव्यवस्था हो, भारत नई सीमाएं खोल रहा है और दुनियाभर में अपने पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।

भारत ने पश्चिमी देशों को बेचा 6.65 अरब डॉलर का रूसी तेल, जामनगर रिफाइनरी का रहा बड़ा हिस्सा

नई दिल्ली। भारत ने पश्चिमी देशों को 6.65 अरब डॉलर के रूसी कच्चे तेल का निर्यात किया है। वहीं, अमेरिका ने भारत से 1.2 अरब यूरो का क्रूड खरीदा है। फिनलैंड की सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने एक रिपोर्ट में कहा, यूक्रेन पर हमले के विरोध में अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने दिसंबर, 2022 में रूसी तेल के आयात का मूल्य दायरा तय कर दिया था। इसके बाद के 13 माह में रूसी क्रूड से शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के भारतीय निर्यात में पश्चिी देशों का हिस्सा एक तिहाई रहा है। इन देशों को भारत ने 6.65 अरब डॉलर का रूसी तेल से निर्यात किया है। जामनगर रिफाइनरी ने 5.2 अरब यूरो का किया निर्यात भारत ने निर्यात के लिए 3.04 अरब यूरो का क्रूड रूस से आयात किया था। पश्चिमी देशों को किए निर्यात में बड़ा हिस्सा जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी का रहा है। इसने 5.2 अरब यूरो का निर्यात किया है। आयात बिल कम करने में मिली मदद सीआरईए ने कहा, भारत ने बीते दो साल में रूस से बड़े पैमाने पर क्रूड का आयात किया है। वह आयातित क्रूड को शोधित कर जी-7 देशों, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात कर रहा है। किफायती दरों पर रूसी क्रूड मिलने से भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिली है।

ऑनलाइन एप से अनधिकृत कर्ज बांटने पर लगाम लगाएं वित्तीय नियामक, निर्मला सीतारमण ने दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई समेत विभिन्न वित्तीय नियामकों को ऑनलाइन एप के जरिये अनधिकृत कर्ज बांटने पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद' (एफएसडीसी) की 28वीं बैठक में कहा, घरेलू और वैश्विक व्यापक वित्तीय स्थिति को देखते हुए उभरते जोखिमों का पता लगाने के लिए वित्तीय नियामक निरंतर निगरानी बनाए रखने के साथसक्रिय रहें। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, बैठक में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनाने के लिए चल रहे अंतर-नियामकीय समेत कईमुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन मुद्दों में एकसमान केवाईसी मानदंड तय करना, वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता और केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण व डिजिटलीकरण शामिल है।

2027 तक भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था; जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली।
भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2047 तक 35 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी बनने के लिए इसे तेज रफ्तार से बढ़ने की जरूरत है। जी20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले तीन दशक तक हर साल 9-10 फीसदी की दर से वृद्धि करने की जरूरत है। नीतिआयोग के पूर्व प्रमुख कांत ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत उस समय से काफी आगे बढ़ चुका है, जब उसे बहीखाते की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आने वाले वर्षों में देश टिकाऊ शहरीकरण, बढ़ी कृषि उत्पादकता व बढ़े निर्यात के दम पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि जापान, ब्रिटेन एवं जर्मनी सभी देशों के मंदी के दौर में चले जाने पर अब हमें लक्ष्य को और अधिक तेजी से पाने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय जीडीपी का आकार मौजूदा मूल्य के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक करीब 3.6 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है।

डीपीआई हमारी बड़ी ताकत

कांत ने कहा, पश्चिमी देशों में सारे नवाचार गूगल, फेसबुक, अमेजन और एपल जैसी कंपनियों से आए। इसके उलट, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) की ताकत को दर्शाया है। यह अर्थव्यवस्था व नवाचार के लिहाज से हमारे लिए बड़ी ताकत बना है।

10 फीसदी विकास दर के लिए निर्यात पर ध्यान देना जरूरी : पनगढ़िया

16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा, भारत को 10 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने के लिए निर्यात पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में औद्योगिक नीति और आयात प्रतिस्थापन के लिए बौद्धिक समर्थन मजबूत बना हुआ है। पनगढ़िया ने कहा, मैंने सिंगापुर, ताइवान, द. कोरिया व भारत जैसे सफल देशों को देखा है। निष्कर्ष स्पष्ट है कि जो देश खुले हैं, वे तेजी से विकसित हुए हैं।

डीपीआई: 2030 तक जीडीपी में देगा 4.2 फीसदी योगदान

आधार, यूपीआई और फास्टैग जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) से मिलने वाले राजस्व ने 2022 में देश की जीडीपी में 0.9 फीसदी योगदान दिया है। इस अवधि में डीपीआई ने कुल 31.8 अरब डॉलर के मूल्य का सृजन किया है। 2030 तक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का जीडीपी में योगदान बढ़कर 2.9-4.2 फीसदी पर पहुंच जाएगा। नैसकॉम और आर्थर डी लिटिल ने रिपोर्ट में कहा, डीपीआई की मूलभूत परतें पारदर्शिता व विश्वास पर आधारित हैं। यह कागजरहित लेनदेन को बढ़ावा देती है। नौकरशाही को कम करती है।

तीसरी तिमाही में घटकर 6 फीसदी रह जाएगी आर्थिक वृद्धि दर : इक्रा

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 2023-24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 6 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। सितंबर तिमाही में विकास दर 7.6 फीसदी रही थी। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन, निवेश गतिविधियों के कुछ संकेतकों की सुस्त रफ्तार, सरकारी खर्च में सुस्ती और मानसून की मार से दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घट सकती है।

अमेरिका से भारत में सेब का निर्यात 16 गुना बढ़ा, 2019 में लगाए गए शुल्क हटाने से मिली वाशिंगटन सफलता

वाशिंगटन।
अमेरिकी सांसद और सेब उत्पादक इस साल भारत में सेबों के निर्यात का जश्न मना रहे हैं। इसका कारण पिछले साल की तुलना में सेब का निर्यात 16 गुना अधिक होना है। भारत के अमेरिकी उत्पादों पर 2019 में लगाए गए 20 प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क को हटाने का फैसला करने के बाद यह निर्यात बढ़ा है।

वाशिंगटन राज्य के सेब उत्पादकों ने इस वर्ष करीब 10 लाख पेटी सेब भारत भेजे, जो गत वर्ष के मुकाबले 16 गुना अधिक है। सिएटल बंदरगाह पर इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। सांसद मारिया केंटवेल ने कहा, यह भारत-अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में एक नया मुकाम है। इस खास मौके पर सिएटल में भारत वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता, मध्य वाशिंगटन के सेब उत्पादक और श्रम व बंदरगाह अधिकारी भी मौजूद थे।

मोदी की यात्रा से कारोबार सामान्य

पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिकी यात्रा में शुल्क हटाने के बाद इस फसल सीजन में कारोबार सामान्य हुआ। वाशिंगटन राज्य सेब आयोग के अनुसार, वाशिंगटन के उत्पादकों ने इस सीजन में करीब 1,190,000 40 पौंड सेब की पेटियां भारत भेजी हैं। अब तक वाशिंगटन से भारत में सेब की कुल बिक्री करीब 1.95 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है, जबकि उत्पादकों ने सीजन केवल आधा ही पूरा किया है। केंटवेल ने कहा, आज एक उत्सव है, क्योंकि गत 5 वर्षों से, हमने सेब को भारत की ओर जाते नहीं देखा है। सेब पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण भारत तक सेब निर्यात बाजार में गिरावट आई थी।

ट्रंप के फैसले का बुरा असर

मार्च 2019 में सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारत के व्यापार लाभों को रद्द करने के तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ नई दिल्ली ने सेब सहित अमेरिकी उत्पादों पर कई टैरिफ लगाए। इसका अमेरिकी कारोबार पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा।

प्रमुख देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक वेतन वृद्धि जारी, इस साल 9.5 फीसदी बढ़ेगी कर्मियों की आय

नई दिल्ली।
देश में इस साल कर्मचारियों का वेतन 9.5 फीसदी बढ़ सकता है। हालांकि, यह 2023 की वास्तविक वेतन वृद्धि 9.7 फीसदी से थोड़ा कम है। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एऑन पीएलसी ने सर्वे रिपोर्ट में कहा, वैश्विक महामारी के बाद 2022 में उच्च वेतन वृद्धि के बाद यह भारत में 10 फीसदी से कम पर स्थिर हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वेतन वृद्धि भारत में जारी है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया में 2024 में क्रमश: 7.3 फीसदी एवं 6.5 फीसदी औसत वेतन वृद्धि का अनुमान है। सर्वे 45 उद्योगों की 1,414 कंपनियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

लक्षित निवेश की जरूरत

एऑन में मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी रूपांक चौधरी ने कहा, भारत के संगठित क्षेत्र में वेतन में अनुमानित वृद्धि उभरते आर्थिक परिदृश्य के सामने एक रणनीतिक समायोजन का संकेत देती है। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की वृद्धि मजबूत है। यह कुछ क्षेत्रों में लक्षित निवेश की जरूरत का संकेत देता है।

इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी संभव

सर्वे के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और जीवन विज्ञान में सबसे अधिक वेतनवृद्धि की उम्मीद है। खुदरा, प्रौद्योगिकी परामर्श व सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन इस साल सबसे कम बढ़ने का अनुमान है। कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 2022 के 21.4 फीसदी से घटकर 2023 में 18.7 फीसदी रह गई।

जी एंटरटेनमेंट में 20 अरब रुपये की हेराफेरी पकड़ी गई, जांच के शुरुआती अनुमान से करीब 10 गुना अधिक

नई दिल्ली।
सोनी समूह के साथ 10 अरब डॉलर का विलय समझौता रद्द होने के एक महीने के भीतर जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लि. को एक और झटका लगा है। बाजार नियामक सेबी ने कंपनी के बहीखाते में 20 अरब रुपये (24 करोड़ डॉलर) की हेराफेरी पकड़ी है। यह आंकड़ा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच के शुरुआती अनुमान से करीब 10 गुना अधिक है। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के लिए जी समूह के संस्थापकों को बुलाया गया है।

बाजार नियामक ने पिछले साल कहा था कि जी समूह के संस्थापक एवं पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे व मौजूदा सीईओ पुनीत गोयनका कंपनी के फंड को समूह की अन्य सूचीबद्ध इकाइयों और इसके संस्थापक शेयरधारकों की कंपनियों में स्थानांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। एक सूत्र ने बताया कि सेबी अप्रैल के मध्य तक अपनी जांच पूरी कर लेगा और उसके बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ब्यूरो

कंपनी का इनकार

जी ने एक बयान में कहा, कंपनी के बहीखाते में गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट अफवाह और गलत है। सेबी की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां मुहैया कराने की प्रक्रिया जारी है। सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका और सेबी ने इस मामले में कोई जवाब देने से इन्कार कर दिया।

इसलिए खत्म हुआ विलय समझौता

सोनी ने नियामकीय कार्रवाई और स्वामित्व विवाद के कारण जी एंटरटेनमेंट के साथ प्रस्तावित विलय समझौते को रद्द कर दिया। विलय के बाद बनी नई कंपनी का सीईओ पुनीत गोयनका को बनाए जाने की बात कही जा रही थी, जिनके खिलाफ सेबी कार्रवाई कर रहा था। इस वजह से सोनी समूह गोयनका को सीईओ नहीं बनाना चाहता था।

शेयरों में गिरावट जारी

जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में गिरावट जारी है। कंपनी का शेयर 14.77 फीसदी टूटकर 164.50 रुपये पर बंद हुआ।

कांग्रेस के खातों से पैसा जब्त करने के लिए बैंकों पर दबाव बनाया, पार्टी ने लगाए ये आरोप

नई दिल्ली।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। बैंकों की ओर से कांग्रेस पार्टी के खातों से राशि जब्त करने पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए बैंकों पर दबाव बनाया गया। बैंकों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, भाजपा सरकार ने बैंकों को हमारी जमा राशि जब्त करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को लगभग 65.89 करोड़ रुपये सरकार को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। यह राशि एआईसीसी और भारतीय युवा कांग्रेस के खाते और एनएसयूआई से है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के विपरीत, हमें यह पैसा पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं से मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट बीजेपी सरकार ने हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वे (भाजपा) बैंकों से हमारा पैसा चुरा रहे हैं।

हमने भी इस देश पर शासन किया। यदि ऐसा कोई उदाहरण है, तो भाजपा बता सकती है कि उनके साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार के दौरान इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो।

क्या भाजपा ने पार्टी के रूप में कोई आयकर दिया है। यह स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर हमला है। और वे भारत के विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से तानाशाही का एक उदाहरण है।

कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसके खातों से 65 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाका डालकर निकाल ली गई ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा सके।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही राज में बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश हो रही है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह कांग्रेस की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। रमेश ने दावा किया कि इस कर आतंकवादी हमले के जरिये यह प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव मजबूती से नहीं लड़ सके।

वेणुगोपाल ने कहा, भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरू किया गया है। हमें यह पैसा आम लोगों और कार्यकर्ताओं से मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के खातों को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, बुनियादी बात है कि बैंकों से हमारे पैसे चुराए जा रहे हैं... यह चुनाव में विपक्ष को समान अवसर से वंचित करने का प्रयास है। वेणुगोपाल ने कहा, हम लड़ेंगे। हम अधिकरण के पास गए हैं... हम जनता के पास जायेंगे, क्योंकि जनता ही मालिक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही राज में बदलना चाहती है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया, भाजपा की सरकार ने सभी विपक्षी दलों और कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरू कर दिया है...हमारे खातों पर डाका डालकर मोदी सरकार पैसे ले गई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से 65,88,81,474 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी. वी. ने आरोप लगाया कि उनके संगठन के खातों से जो पैसा निकाला गया, वह कार्यकर्ताओं ने जमा किया था।

उन्होंने कहा कि जनता इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का जवाब देगी। आयकर विभाग ने पिछले दिनों 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रमुख खाते 'फ्रीज' कर दिए थे। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगली सुनवाई होने तक उसके खातों पर से रोक हटा दी थी।

बेयरस्टो की जगह लारेंस को शामिल करें : कुक

लंदन।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ रांची में शुरु हो रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को नहीं रखा जाना चाहिये। कुक के अनुसार बेयरस्टो का प्रदर्शन इस सीरीज में अच्छा नहीं रहा है। वह पिछली छह पारियों में एक बार भी 40 रनों तक भी नहीं पहुंच पाये हैं। उनका औसत भी 17.00 बेहद खराब रहा है।

कुक ने कहा, 'मैं इस खिलाड़ी की भलाई के लिए ही उसे बल्लेबाजी लाइन अप से बाहर करने की बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक भारत का दौरा उसके लिए कठिन साबित हुआ है। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह फिर कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा पर अभी ये अच्छा रहेगा कि किसी ऐसे किसी खिलाड़ी को अवसर दिया जाये जिसने अब तक इस सीरीज में नहीं खेला है। कुक ने बेयरस्टो की जगह पर डैन लारेंस को शामिल करने का सुझाव भी दिया।

उन्होंने कहा, 'जब आप रन नहीं बना पा रहे हों तो कुछ गेंदबाज आपके खिलाफ दबाव बनाकर लय बना लेते हैं, इसलिये मैं लारेंस को शामिल करने के पक्ष में हूं। वहीं एक अन्य पूर्व कप्तान माइकल एथरटन का मानना है कि इंग्लैंड टीम प्रबंधन बेयरस्टो को ही रखेगा। एथरटन ने कहा, 'बेयरस्टो इस सीरीज के लिए अबतक अहम रहा है इसलिये मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर उसे बाहर कर दिया जाएगा।

इंग्लैंड की टीम अभी पांच मैच की इस सीरीज में अभी 1-2 से पीछे है और ऐसे में चौथा टेस्ट उसके लिए बेहद अहम है। कुक के अनुसार जिस प्रकार भारतीय टीम ने अपने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। उसी प्रकार उनकी टीम को भी अपने तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और मार्क वुड को आराम देना चाहिये। इससे वे अंतिम टेस्ट में तरोताजा होकर उतर सकेंगे। इस सीरीज का अंतिम धर्मशाला में होगा और वहां के हालात तेज गेंदबाजों के अनुकूल माने जाते हैं। ऐसे में एंडरसन और वुड धर्मशाला के ठंडी हालातों में काफी प्रभावी होंगे। कुक ने इन दोनों की जगह रांची में ओली रोबिन्सन और 'अनकैप्ड गुस एटिकिन्सन को अवसर दिये जाने की सलाह दी है।

न्यूज ब्रीफ

ऑस्ट्रेलिया की योजनाओं में स्मिथ की दृढ़ता से पुष्टि की

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि स्टीव स्मिथ कैरेबियन और यूएसए में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप के लिए मजबूती से टीम में शामिल हैं। वेलिंगटन में श्रृंखला के शुरुआती एकादश में शामिल नहीं होने के बाद स्मिथ के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शेष दो मैचों में से कम से कम एक में ओपनिंग करने की संभावना है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक तरीके से 6 विकेट से जीता था। टी20 सेटअप में स्मिथ की स्थिति के बारे में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर पिछले साल के अंत से टी20ई से उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए। विश्व कप में शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे कई अन्य दावेदारों ने उनके सामने अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे उनकी भूमिका को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ गई है। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत के बाद बोलते हुए, मैकडॉनल्ड्स ने पुष्टि की कि स्मिथ ऑकलैंड में बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संकेत दिया कि उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में नई भूमिका में मौका मिलेगा, संभावित रूप से डेविड वार्नर के साथ जोड़ी बनाई जाएगी क्योंकि थिंक टैंक अपनी रणनीति को परिष्कृत कर रहा है। जून में विश्व कप। अगर वह हमारी सोच में नहीं होता तो वह यहां विमान में नहीं होता। हम उसे एक कारण से खेल रहे हैं। उसे यहां कुछ अवसर मिलेंगे, उसके पास भारत में कुछ अवसर थे। विश्व कप और हम उसके लिए अगस्त-सितंबर (पिछले साल) में दक्षिण अफ्रीका में खेलने की योजना बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय उसकी कलाई में चोट लग गई थी, इसलिए वह उन तीन एकदिवसीय मैचों में नहीं खेल पाया मैक्डोनाल्ड द्वारा उद्धृत किया गया था। लेकिन वह निश्चित रूप से विचारों में है। हम शायद उसे टी20 क्रिकेट में पिछले विश्व कप में देखी गई भूमिका से थोड़ी अलग भूमिका में निभाएंगे। वह हाल के दिनों में शीर्ष क्रम में गया है, इसलिए ऊपर बल्लेबाजी करना जरूरी है। अभी भी स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी समस्या है, उन्होंने कहा। जून की शुरुआत में विश्व कप शुरू होने पर वार्नर और हेड द्वारा शुरुआती साझेदारी बनाने की उम्मीद है।

एंजेलो परेरा होंगे राजस्थान लीजेंड्स के और मुनाफ पटेल होंगे छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के कप्तान

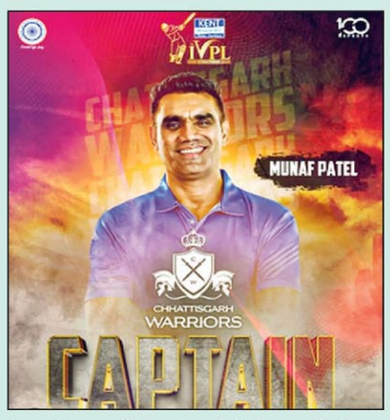

ग्रेटर नोएडा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर एंजेलो परेरा इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग (आईवीपीएल) के उद्घाटन संस्करण में राजस्थान लीजेंड्स जबकि विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल छत्तीसगढ़ वॉरियर्स का नेतृत्व करेंगे। इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग (आईवीपीएल) का उद्घाटन संस्करण, जो शुक्रवार से यहां शुरू होने वाला है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत परेरा के साथ मिलकर राजस्थान लीजेंड्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण को तेज गेंदबाज परविंदर अवाना के साथ मजबूत करेंगे। इसी बीच भारत के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी मुनाफ पटेल क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने और आईवीपीएल में दिग्गज खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक हैं। मुनाफ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, मुझे मैदान पर वापस आकर इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स का नेतृत्व करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिकेट हमेशा से मेरा जुनून रहा है और मैं फिर से खेलने के लिए उत्साहित हूं। मैं आईवीपीएल को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया (बीवीसीआई) द्वारा आयोजित और 100 स्पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित, आईवीपीएल में वीरेंद्र सहवाग, मुनाफ पटेल, सुरेश रैना, रजत भाटिया, क्रिस गेल, प्रवीण कुमार और हर्षल गिब्स जैसे दिग्गज एक साथ दिखेंगे। भाग लेने वाली टीमों में वीवीआईपी उत्तर प्रदेश, राजस्थान लीजेंड्स, रेड कार्पेट दिल्ली, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, तेलंगाना टाइगर्स और मुंबई चैंपियंस शामिल हैं। इस बीच टीमों ने आईवीपीएल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सुरेश रैना की अगुवाई वाली वीवीआईपी उत्तरप्रदेश ने यहां क्रिकेट स्टेडियम में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया।

मेग लैनिंग से सीखने के लिए बहुत कुछ है : जेमिमा रोड्रिग्स

बेंगलुरु।

दिल्ली कैपिटल्स की उप-कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि कप्तान मेग लैनिंग से हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वह महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान के साथ काम करने का मौका दिया। यह बहुत अच्छा लगता है। उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। वह ऐसी व्यक्ति है जो सम्मान की मांग नहीं करती है, वह बस चली जाती है और हर कोई उसके लिए स्वचालित रूप से सम्मान करता है। उसने बहुत कुछ किया है, यही कारण है कि हमारे मन में उसके लिए इतना सम्मान है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनके साथ करीब से और व्यक्तिगत रूप से काम करते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वह अवसर मिलेगा। डब्ल्यूपीएल का धन्यवाद, मुझे यह मिल रहा है।

जेमिमा ने ब्रॉडकास्टर्स जियोसिनेमा से कहा, उप-कप्तान होने के नाते, मैं कई निर्णयों में शामिल हूं, यह देखते हुए कि वह कैसे काम करती है। हाल ही में, मैंने उनसे कप्तानी के बारे में बात की और उन्होंने इसे कैसे संभाला क्योंकि उन्हें कम उम्र में कप्तान बनाया गया था। कप्तानी बहुत अधिक है। मैदान के बजाय मैदान के बाहर, आपको बहुत सी चीजें संभालनी होती हैं।

फिर मैदान के बाहर, आपकी अपनी बल्लेबाजी और आप इसे कैसे करते हैं। यह एक अच्छी बातचीत थी और मुझे यकीन है कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह नेतृत्व की जिम्मेदारियों से अभिभूत हैं, जेमिमा ने कहा: अब तक मुझे ऐसी स्थिति में नहीं रखा गया है जहां मेग को मैदान से बाहर जाना पड़े और मुझे पहल करनी पड़े। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। अपनी टीम को जानते हुए , वे मेरे लिए इसे आसान बना देंगे। बड़े होते हुए, मैं हमेशा मुंबई टीम में रही हूं और बहुत कम उम्र में नेतृत्व करते हुए वरिष्ठों के साथ काम किया है। यह उससे बहुत अलग है लेकिन कुछ हद तक समान है और वह अनुभव यहां मिलेगा। मैंने इस बारे में मेग से बात की थी और मैं सभी सलाह का उपयोग करूंगी।

जेमिमा ने 2023 डब्ल्यूपीएल फाइनल में मुंबई इंडियंस से कैपिटल्स की हार के बाद के कठिन समय के बारे में भी बात की। यह कठिन था। हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे पास कुछ अद्भुत मैच थे। जिसे हम वास्तव में सबसे अधिक जीतना चाहते थे, वह हमारे पक्ष में नहीं गया लेकिन वह खेल है। इसलिए हम खेलना पसंद करते हैं। आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। यह आपको बहुत कुछ सिखाता है, वापस खड़े होना और आपको हमेशा एक और मौका देता है। यह हमारा दूसरा मौका है। उम्मीद है कि इस साल अपने घरेलू मैदान पर हम डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी उठाएंगे। कभी-कभी ऐसा गेंदबाज होता है जिसे मैं आमतौर पर हिट कर सकती हूं लेकिन वह अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो मैं उसे समझदारी से खेलूंगी। मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतना चाहती हूं और मेरे पास प्रतिस्पर्धात्मकता है, लेकिन मैं योग्यता और स्थिति के अनुसार खेलूंगी।

डीसी टीम में नए खिलाड़ियों के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर जेमिमा ने एनाबेल सदरलैंड और अश्विनी कुमारी पर अपने विचार व्यक्त किए। हमें एनाबेल सदरलैंड मिल गई है। उसने हाल ही में दोहरा शतक बनाया है और गेंद के साथ भी अद्भुत समय बिताया है। मैंने डब्ल्यूबीबीएल में उसके साथ खेला है, और वह एक महान व्यक्ति है, एक बहुत अच्छी क्षेत्ररक्षक है। एक कप्तान के रूप में, वह एक ऐसी खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे क्योंकि वह सभी पहलुओं को कवर करती है। हमारे पास अश्विनी (कुमारी) है, एक और युवा प्रतिभा आ रही है और फिनिशर की भूमिका निभा रही है जिसे हम तलाश रहे हैं। वह ऐसी व्यक्ति है जो सीखना और बेहतर बनना चाहती है।

यही उसका सबसे बड़ा गुण है। जब दिल्ली डब्लूपीएल 2024 का दूसरा भाग खेलने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में आएगी तो जेमिमा ने भीड़ के समर्थन की उम्मीद करते हुए कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं। अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने जैसा कुछ नहीं है। मैं एक मुंबईवासी हूं और मुंबई में दिल्ली की जर्सी पहन रही हूं, मेरे परिवार को छोड़कर हर कोई मुंबई इंडियंस का समर्थन कर रहा था।

हालैंड के गोल से सिटी ने ब्रेंटफोर्ड पर दर्ज की जीत, दूसरे हाफ में गोल दाग 1-0 से जिताया मैच

मैनचेस्टर।

एक समय ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी लगातार दूसरा मुकाबला ड्रॉ खेलने जा रहा है, लेकिन एर्लिंग हालैंड ने खेल के 71वें मिनट में गोलकर सिटी को ब्रेंटफोर्ड पर 1-0 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष पर मौजूद लिवरपूल (57) और सिटी (56) के बीच सिर्फ एक अंक का फासला रह गया है। आर्सेनल 55 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है और सिटी से एक अंक पीछे हैं। तीनों टीमों ने 38 में से 25-25 मैच खेले हैं।

पहला हाफ गोलरहित रहा

सिटी ने पिछले मैच में चेल्सी के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। यहां भी कोच पेप गॉर्डिओला की योजनाएं सफल होती नहीं दिखाई दे रही थीं। पहला हाफ गोलरहित छूटा था और दूसरे हाफ की शुरुआत में भी सिटी को गोल को नसीब नहीं हुआ था, लेकिन पिछले सत्र के शीर्ष स्कोरर और मैनचेस्टर सिटी को लीग का खिताब जिताने में मुख्य भूमिका निभाने वाले हालैंड एक बार फिर टीम के लिए संकटमोचक साबित हुए। जूलियन अल्वारेज ने हालैंड को गेंद दी। उन्होंने सेंटर बैक क्रिस्टोफर अजेर को छकाते हुए गोल भेदा। यह उनका सत्र में 17वां गोल रहा।

16 मैचों से अपराजेय है सिटी

प्रीमियर लीग में पिछले सत्र में हालैंड 21 टीमों के खिलाफ खेले हैं, लेकिन ब्रेंटफोर्ड एक ऐसी टीम थी, जिसके खिलाफ उन्होंने गोल नहीं किया था। हालैंड के सिटी और नॉर्वे के साथी ऑस्कर बॉब ने कहा कि हालैंड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस जीत के साथ सिटी का सभी कंपटीशनों में छह दिसंबर से अपराजेय रहने का सिलसिला 16 मैच तक पहुंच गया है। इस दौरान उसने 14 मैच जीते हैं और दो ड्रॉ खेले हैं। सिटी की टीम एफए कप के अंतिम-16 में पहुंच चुकी है। चैंपियंस लीग के भी उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल हैं।

सचिन ने कश्मीर में युवाओं के साथ क्रिकेट खेला

श्रीनगर।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आजकल अपने परिवार के साथ कश्मीर घाटी के दौरे पर हैं। इस दौरान सचिन ने बर्फबारी का आनंद लेने के साथ ही स्थानीय युवकों के साथ क्रिकेट भी खेला जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। इसमें सचिन उरी में कुछ स्थानीय युवकों के साथ सड़क किनारे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान ये युवा सचिन के फुटवर्क और उनके शॉट लगाने के तरीके को देखते नजर आये। तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा क्रिकेट और कश्मीर, स्वर्ग में एक मैच।

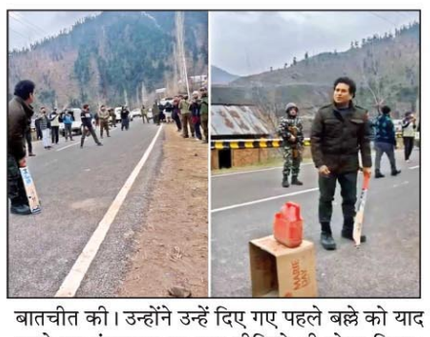

वहीं कुछ दिन पहले ही उन्होंने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुर्सू में एक क्रिकेट बैट निर्माण इकाई का भी दौरा किया था। तेंदुलकर ने विनिर्माण इकाई में एक घंटा बिताया और प्रशंसकों के एक छोटे समूह से बातचीत की। उन्होंने उन्हें दिए गए पहले बल्ले को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे पहला बल्ला मेरी बहन ने दिया था और वह कश्मीर विलो बल्ला था। अब मैं यहां हूं तो कश्मीर विलो को तो मिलना बनता है।

सचिन ने उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आखिरी बिंदु अमन सेतु पुल का दौरा किया और जवानों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि लगभग एक घंटे तक चली अपनी यात्रा के दौरान तेंदुलकर ने अमन सेतु के पास कमान पोस्ट पर सैनिकों से बातचीत की। इसके अलावा वह दक्षिण कश्मीर के पहलगाम पर्यटन स्थल भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य वीडियो में तेंदुलकर को एक उड़ान में अपने साथी यात्रियों से उत्साहित होकर बात करते हुए देखा गया। इस दौरान यात्रियों ने तालियां बजाईं और सचिन-सचिन के नारे लगाए। इसपर सचिन ने भी उनका अभिवादन किया।

साइक्लिंग चैंपियनशिप : बेटियों ने एशियाई जूनियर साइक्लिंग में जीता सोना, भारत ने पहले दिन जीते चार पदक

नई दिल्ली।

बेटियों ने एशियाई साइक्लिंग चैंपियनशिप में भारत को स्वर्णिम शुरुआत दिलाई। आईजी स्टेडियम वेलड्रोम में जूनियर वर्ग में सरिता कुमारी, निया सेबेस्टियन, जायना मोहम्मद अली पीरखान और सबीना ने स्प्रिंट इवेंट में मजबूत कोरिया को हराकर चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। भारत ने एक रजत पैरा टीम स्प्रिंट इवेंट में, दूसरा रजत पुरुषों की जूनियर टीम स्प्रिंट इवेंट में जीता, जबकि कांस्य पदक लड़कियों की जूनियर टीम परस्यूट इवेंट में मिला।

अंतिम रेस में कोच ने बदला रायडर

स्प्रिंट टीम के कोच राहुल के मुताबिक उन्होंने रणनीति के तहत तीसरी और अंतिम रेस में सबीना की जगह पर जायना को उतारा, जिसका फायदा मिला। जायना थकी हुई नहीं थीं, जिसके चलते भारत ने 53.383 सेकंड का समय निकाला, जो कोरियाई रायडरों से बेहतर था। राहुल के मुताबिक उन्होंने पहली दो रेस में सरिता, निया और सबीना को उतारा था।

तीसरी रेस में कोरिया रायडर के फाल्स स्टार्ट का भी भारतीय टीम को फायदा मिला। केरल की निया ने कहा कि एशिया की सबसे मजबूत टीम को हराना किसी सपने के सच होने जैसा है।

18 देश शिरकत कर रहे हैं

सीनियर और जूनियर वर्ग में हो रही पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग इस चैंपियनशिप में 18 देश शिरकत कर रहे हैं। पैरा टीम स्प्रिंट में अरशद शेख, जलालुद्दीन अंसारी, बासवाराज की टीम को फाइनल में मलयेशिया से हार का सामना करना पड़ा। जूनियर वर्ग की पुरुष टीम स्प्रिंट में नारायण महतो, सैयद खालिद बागी, एम वताबा मितेई की तिकड़ी ने 47.93 सेकंड का समय लिया, लेकिन कोरियाई टीम ने उनसे बेहतर समय निकालकर स्वर्ण जीता। जूनियर परस्यूट में हर्षिता जाखड़, सुहानी कुमारी, जेपी धन्याधा, भूमिका ने ताइवान को हराकर कांस्य जीता।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स

ऐश्वर्य ने जीते दो स्वर्ण पदक, शूटर ने 10 मीटर एयर राइफल में दर्ज की श्रेष्ठता

गुवाहाटी।

हांगझोऊ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दोहरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के ऐश्वर्य ने पहले 10 मीटर एयर राइफल का व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। इसके बाद उन्होंने विदित जैन और मनप्रीत सिंह बसरा के साथ मिलकर इस स्पर्धा का टीम स्वर्ण भी अपने नाम किया। जैन यूनिवर्सिटी का इन खेलों में दबदबा जारी है। सात स्वर्ण पदक के साथ यह यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर है।

जैन यूनिवर्सिटी को बास्केबाल का स्वर्ण

ऐश्वर्य 10 मीटर एयर राइफल के क्वालिफाइंग दौर में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन फाइनल में उन्होंने 252 का स्कोर कर एम उमामहेश को 2.1 के अंतर से हराया।

1871.7 के कुल योग के साथ जीएनडीयू ने इस स्पर्धा का टीम स्वर्ण भी जीता। ऐश्वर्य ने कहा कि वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उन्होंने ग्रेनाडा विश्वकप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन यहां उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया।

जैन यूनिवर्सिटी ने महिला बास्केटबाल के फाइनल में मद्रास यूनिवर्सिटी को 68-58 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कबड्डी का स्वर्ण

चार स्वर्ण, छह रजत और आठ कांस्य के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। वेटलिफ्टिंग में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की तृप्ति माने ने 76 भार वर्ग में 177 किलो वजन के साथ स्वर्ण जीता। इसी यूनिवर्सिटी के अभिजीत दिसाले ने 89 भार वर्ग में 302 किलो वजन उठाकर स्वर्ण जीता। जीएनडीयू के सुरिंदर पाल ने रजत जीता। महिला कबड्डी के फाइनल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भारती विद्यापीठ को 34-32 से हराकर स्वर्ण जीता।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और खेलों से जुड़ी सुविधाओं के मिलने से इस केंद्र शासित प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के शहरों और गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में खेलों के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से खेल क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन मिला है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे।

से बढ़ती है उम्र

अध्ययन से साबित हुआ कि शारीरिक सक्रियता लंबी उम्र के लिए फायदेमंद होती है। यदि 40 की उम्र में कोई व्यक्ति हर हफ्ते औसतन 75 मिनट तक सैर करता है तो वह करीब 1.8 साल ज्यादा जीता है। वहीं हर हफ्ते 450 मिनट सैर करने वाले अपेक्षाकृत साढ़ेचार साल ज्यादा जीते हैं। हर हफ्ते 75 मिनट पैदल चलने वालों की मृत्युदर में 17 फीसद की गिरावट देखी गई। करीब छह लाख 50 हजार लोगों और 82 हजार मौतों पर हुए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।

सैर करने से सेहत अच्छी रहती है यह तो आपने सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की मानें तो तेज कदमों से टहलने से आपकी उम्र करीब दो साल तक बढ़ जाती है।

ब्राइगहैम एंड वुमेंस हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किए गए अपने शोध में यह बात कही है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और उनके बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर अध्ययन किया।

अध्ययन से साबित हुआ कि शारीरिक सक्रियता लंबी उम्र के लिए फायदेमंद होती है। यदि 40 की उम्र में कोई व्यक्ति हर हफ्ते औसतन 75 मिनट तक सैर करता है तो वह करीब 1.8 साल ज्यादा जीता है। वहीं हर हफ्ते 450 मिनट सैर करने वाले अपेक्षाकृत साढ़े चार साल ज्यादा जीते हैं। हर हफ्ते 75 मिनट पैदल चलने वालों की मृत्युदर में 17 फीसद की गिरावट देखी गई। करीब छह लाख 50 हजार लोगों और 82 हजार मौतों पर हुए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। उनका कहना है कि निरंतर पैदल चलने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है।

पैदल चलना हमेशा से स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। खासकर हृदयरोगियों को भी कोई अन्य कसरत न कर पाने की स्थिति में भी चिकित्सक उन्हें नियमित चहलकदमी करने की सलाह देते हैं। इससे उनका रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है।

वैसे तो आप लहसुन खाने में रोजाना ही थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपको कितनी बीमारियों से बचाता है। लहसुन के इन्हीं गुणों को जानने के लिए पढ़िए ये स्टोरी। लहसुन के तमाम गुणों जानें एवं उनका समय-समय पर लहसुन का उपयोग करें। लहसुन में ये फायदे हैं -

दिल को रखता है दुरूस्त

अगर आप दिल की बीमारियों से परेशान हैं तो लहसुन आपको इनसे बड़ी ही आसानी से छुटकारा दिला सकता है। इसमें खून को पतला करने का गुण पाया जाता है। ये दिल के दौरों को पड़ने से रोकता है।

एक एंटीऑक्सीडेंट

लहसुन में जो एलिसिन पाया जाता है वो निकोटीन के प्रभाव को कम करता है इसलिए स्मोकरस को लहसुन सुबह चबाने की राय दी जाती है।

एंटीबैक्टिरीयल

लहसुन एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल है। अगर आपको कोई ऐस इंफेक्शन है जो बार- बार परेशान कर रहा है तो लहसुन का प्रयोग फायदेमंद होता है।

खून का थक्का बनने से रोकता है

ये बात कई क्लीनिकल ट्रॉयल में सामने आ चुकी है कि अगर किसी का ब्लड प्रैसर बढ़ रहा है और उसने लहसुन से बना कोई भी सप्लीमेंट ले लिया तो उसका ब्लड प्रैसर 1-5 प्रतिशत तक कम हो सकता है। ब्लड प्रैसर में इतनी कमी ही आपको दिल के दौरे से 30-40 प्रतिशत तक निजात दिला सकती है।

एंटीसेप्टिक

लहसुन का ये गुण तो लोग सदियों से बताते चले आये हैं। अगर कोई आदमी घायल है तो आप लहसुन की मात्रा उसके खाने में थोड़ी बढ़ा दीजिए और फिर उसका घाव बहुत जल्दी भरना शुरू हो जायेगा।

कॉलेस्ट्रोल को कम करता है

कॉलेस्ट्रोल की समस्या से परेशान लोगों के लिए लहसुन का नियमित सेवन अमृत साबित हो सकता है।

हाई ब्लड प्रैसर में उपयोगी

उच्च रक्त चाप में लहसुन बहुत उपयोगी माना जाता है। लहसुन में पाया जाने वाला सल्फाइड हाई ब्लड प्रैसर को कम करने में काफी मदद करता है। ये सल्फाइड लहसुन को पकाने के दौरान भी नष्ट नहीं होते। इसलिए आप सब्जी और दाल में झोंक लगाते वक्त भी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इससे इसमें पाये जाने वाले सल्फाइड नष्ट नहीं होते।

मुंहासों से बचाता लहसुन

अक्सर युवाओं को मुहासे परेशान करते रहते हैं। ये शरीर में हार्मोनल चेंज, पेट की खराबी की वजह से हो सकते हैं। मुंहासों में लहसुन बहुत ही कारगर साबित होता है।

कफ में लहसुन लाभदायक

ठंड या बदलते मौसम में अक्सर किसी भी उम्र के लोगों को कफ और जुकाम जैसी परेशानी हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप लहसुन का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आप ऐसी छोटी-छोटी समस्याओं से बड़ी ही आसानी से निजात पा सकते हैं।

कैंसर के खतरे को कम करता है

लहसुन में जर्मेनियम तत्व पाया जाता है जो एंटी कैंसर के रूप में काम करता है। कैंसर के इलाज में भी डॉक्टरस लहसुन की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं।

प्रतिदिन लहसुन की एक कली के सेवन से शरीर को विटामिन ए, बी और सी के साथ आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्निशयम जैसे कई पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं।

शुभदा बताती हैं कि अगर आप लहसुन की 2-3 की कलियों को पीसकर गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये आपको ओवरवेट की समस्या से छूटकारा दिलायेगा।

बच्चों की रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन को पीसकर दूध में उबालकर पिलायें। लहसुन की कलियों को तवे पर भूनकर बच्चों को खिलाने से सांस की तकलीफ दूर होती है। ये 3-4 कलियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर किसी विषैले कीड़े ने आप को काट लिया है तो लहसुन को पीसकर उसको लगा लें। याद रहे गर्मी में एक घंण्टे से ज्यादा समय तक इसे त्वचा पर नही लगायें।

इन्फलूएंजा में एक लहसुन का रस पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से फायदा होगा।

डायबिटीज के मरीजों को अगर लहसुन और त्रिफला का 20-25 ग्राम रस सुबह-सुबह प्रयोग करने से काफी हद तक राहत मिलती है।

लकवा में मांसपेशियों को पुन: सक्रिय करने में लहसुन के तेल की मालिश फायदेमंद होती है।

अगर आपको इसकी गंध अच्छी नहीं लगती तो आप दिन में गार्लिक की 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हैं।

गला बैठ रहा है तो गुनगुने पानी में लहसुन का रस मिलाकर गरारे करें, गला ठीक हो जायेगा।

कुछ सावधानियां

बेशक लहसुन कुदरती खूबियों से भरपूर है। लेकिन इसे उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। लहसुन की तासीर काफी गर्म और खुश्क होती है कुछ लोगों को रास नही आती। इसलिए इसका इस्तेमाल संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए खासकर गर्मियों में।

अगर एक या दो लहसुन की लौंग का इस्तेमाल करने पर भी इसका कोई साइडइफेक्ट हो तो इसके लिए अपने डाक्टर से सलाह लें। अगर आपको कोई बीमारी है तो लहसुन का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

मौसम के हिसाब से लहसुन को खाने में बदलाव करें। जाड़ों में लहसुन अधिक मात्रा में खाया जा सकता है लेकिन गर्मी में इसकी मात्रा सीमित करें।

नेजल पॉलिप नाक में नहीं करेगा दम

मौसम का मिजाज बदलने के साथ कई बार उसका असर आपकी नाक पर भी पड़ता है। नाक बद होने लगती है और कभी-कभी सास लेने भी दिक्कत होने लगती है।

हालाकि नाक से जुडी ये समस्याएं अल्पकालिक होती हैं और मामूली दवाओं के सेवन से इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। फिर भी अगर आपकी यह तकलीफ दवाएं लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो सतर्क हो जाइये क्योंकि आप नेजल पॉलिप रोग का शिकार हो गये हैं।

रोग का स्वरूप

नेजल पॉलिप में नाक के भीतर का मास बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप नाक बद होने लगती है, सूंघने की क्षमता घटती जाती है और कई बार नाक से पानी भी आने लगता है। अब बड़ी सख्या में इस रोग से युवक भी ग्रस्त हो रहे हैं।

इलाज

एलर्जी और सक्रमण की वजह से होने वाली इस बीमारी का उपचार समय रहते करा लेना चाहिए, अन्यथा यह रोग पीड़ित व्यक्ति की आख और मस्तिष्क पर भी बुरा असर डाल सकता है। इस सदर्भ में सुखद बात यह है कि नेजल पॉलिप अब लाइलाज बीमारी नहीं रह गयी है। पीड़ित व्यक्ति सिर्फ दो दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है।

सबसे पहले रोगी का सीटी स्कैन करके पता किया जाता है कि नाक में मास कितना बढ़ चुका है। फिर इंडोस्कोपिक सर्जरी के जरिये साइनस के भीतर के भाग को खोल देते हैं ताकि अंदर हवा जाने लगे। इस बीमारी को ठीक करने के लिए कई तरह के इलाज के दावे किये जाते हैं, लेकिन अभी तक सर्जरी ही सबसे कारगर इलाज है। यह सर्जरी ज्यादा महंगी भी नहीं है।

न्यूमोनिया से ऐसे बचें

मौजूदा मौसम में खासकर 5 से 7 साल तक के बच्चों में न्यूमोनिया रोग वयस्कों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। बच्चों के अभिभावक अगर सजगता बरतें, तो उनके लाड़ले या लाड़ली का न्यूमोनिया से काफी बचाव हो सकता है।

1. बच्चों को बदलते हुए तापमान से बचाएं। जैसे उन्हें सोने वाले कमरे से तुरंत खुली हवा में न लाएं।
2. नवजात बच्चों को कम से कम ऊनी कपड़ों की दो परत पहनाएं। इसके अलावा उन्हें मौजे, दस्ताने व ऊनी कैप जरूर पहनाएं।
3. कमरे को गर्म रखने के लिए अंगीठी या लकड़ी आदि न जलाएं, क्योंकि इन वस्तुओं का धुआ बच्चे के फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है।
4. घर के जो सदस्य पहले से ही सर्दी-जुकाम आदि सक्रमण वाले रोगों से ग्रस्त है, उन्हें छोटे बच्चों से दूर रहना चाहिए ताकि वे संक्रमण से बच सकें।
5. बच्चों में सास तेज चलना, पसली चलना या साय-साय की आवाज आना या फिर शरीर का नीला पड़ना आदि लक्षणों के प्रकट होती ही डॉक्टर से संपर्क करें।

गंजापन भी है हार्ट अटैक की निशानी

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर नजर आने वाली बुढ़ापे की निशानिया भी दरअसल हार्ट अटैक आने का संकेत होता है। गंजापन, आखों के नीचे झुर्रियां और आंख के नीचे त्वचा लटकने से थैली बनना भी हृदय रोग होने का अलार्म है। एक नए शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जिन लोगों में बुढ़ापे के तीन से चार चिन्ह नजर आने लगते हैं वह दिल का दौरा पड़ने के मुहाने पर हैं। इन चिन्हों में कनपटी के पास बाल कम होना, सिर की चाद से बालों का कम होना, कान के आगे का गाल उभरना और पलकों के नीचे पीलापन लिए फूली हुई चर्बी नजर आना शामिल है। इन लक्षणों वाले लोगों को हार्ट अटैक आने का 57 फीसद खतरा होता है। साथ ही उनमें दिल संबंध अन्य रोग होने का भी 39 फीसद अंदेशा होता है। उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षण दरअसल शारीरिक और जैविक अक्षमताओं की निशानी होते हैं। उनका सीधे तौर पर व्यक्ति की असली उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता है।

डेनमार्क में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री की प्रोफेसर एनी टायबर्ग हैनसेन का कहना है कि अनुसंधानकर्ताओं ने कोपेनहेगन हार्ट स्टडी में 10,885 प्रतिभागियों पर शोध किया जिनकी उम्र 40 साल या इससे ऊपर की थी। इसमें 45 फीसद महिलाएं थीं। इनमें 7537 लोगों को कनपटी के पास से बाल झड़ने की शिकायत थी। 3938 लोगों की चाद साफ हो रही थी। 3405 लोगों के कान के आगे के गाल उभर गए वहीं 678 लोगों की आखों के नीचे पीलापन लिए थैली बन गई। 35 साल तक इन पर शोध के बाद पाया गया कि इनमें से ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारिया हुई थीं।

बचपन में पिया दूध बुढ़ापे के लिए बेहतर

बचपन में हमेशा दूध पीने वाले बच्चों का बुढ़ापा बहुत सेहतमंद और चुस्त-दुरुस्त रहता है। शोध के अनुसार बचपन में पिया दूध लोगों को जीवन के आखिरी पड़ाव में काम आता है।

ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं के जिन बुजुर्ग लोगों ने अपने बचपन में नियमित रूप से दूध पिया था और दुग्ध उत्पादों का सेवन किया था वह जल्दी चल पाते थे और उन्हें शारीरिक बीमारियां भी कम थीं। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार बच्चे के दूध पीने और उसके शारीरिक विकास की तुलना वाला यह पहला शोध है। 60 बरस से अधिक उम्र के 400 पुरुष और महिलाओं पर अनुसंधानकर्ताओं ने ये अध्ययन किया। उन्होंने शोध में पाया कि 1930 के दशक में जन्मे लोगों को दूध पीने की आदत बहुत फली। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि वह तेज चल सकते थे और उनका शारीरिक संतुलन भी अन्य बुजुर्गों के मुकाबले अधिक था।

दूध पीने वाले बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिससे उनकी हड्डिया मजबूत हो जाती हैं। साथ ही विटामिन डी के कारण उनको जोड़ों का दर्द भी नहीं होता है। बुढ़ापे में इससे उनकी चाल-ढाल सामान्य बनी रहती है। उन्हें छड़ी का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। ये शोध एज और एजिंग पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**